प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

हर किसी पर विश्वास कर लेना खतरनाक है, किसी पर भी विश्वास न करना बहुत खतरनाक है।

अब्राहम लिंकन

वर्ष-08, अंक - 14 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 08 जनवरी 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

स्वच्छता के दामन पर दुषित पेयजल का कलंक...

माही के गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल महत्वपूर्ण बिंदु है और स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इंदौर जिसका नाम सामने आते ही एक स्वच्छ और सुंदर शहर की तस्वीर आम भारतीय नागरिक के जेहन में आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न मंचों से इंदौर का नाम बड़े गर्व के साथ लेते थे... वह इंदौर जो स्वच्छता के मामले में अन्य शहरों के लिए आदर्श था... वह इंदौर जहां के नागरिक स्व अनुशासित होकर स्वच्छता का पाठ अन्य लोगों को सिखाते थे। उसी इंदौर के दामन पर दूषित पेयजल वितरण और उससे हुई मौतो ने ऐसा कलंक लगाया है जो निकट भविष्य में धुलना या भूला पाना मुश्किल है।

मध्यप्रदेश में नौकरशाही हावी है और आम जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है। इस प्रकार की खबरें माही की गूंज ने कई बार उठाई लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ये घटना इंदौर जैसे महानगर की थी और कई लोग मौत के मुंह में चले गए इसलिए यह घटना सामने आ गई अन्यथा प्रशासनिक इस घटना को भी बाहर नहीं आने देते। ऐसे कई मामले हुए हैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने दबंगता दिखाते हुए मामले को रफा-दफा करवा दिया। कुछ समय पूर्व थांदला क्षेत्र के एक ग्राम में कुएं का दूषित जल पीने से सैकड़ो लोग उल्टी-दस्त के शिकार हुए थे लेकिन प्रशासन ने मुस्तेदी दिखाते हुए उस घटना का दूषित पेयजल माना ही नहीं, अन्य मामला बताकर तथा बीमारो का उपचार कर मामले को रफा-दफा कर दिया। जबकि प्रशासन को चाहिए था कि, वो उक्त घटना से सबक लेकर अपनी व्यवस्था दुरुस्त करता जिससे इंदौर जैसी घटना घटित नहीं हो पाती। लेकिन प्रशासनिक अफसर अपनी वाहवाही बताने में पीछे नहीं हटते हैं और सही को गलत और गलत को सही बनाने में भी संकोच नहीं करते हैं। बताया जाता है कि, उक्त घटना के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ पूरी रात मोटर चलाकर कुएं को खाली करवा लिया था और तत्काल ट्यूबवेल से दूसरा पानी भर दिया था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उस कुएं से साफ पानी के सैंपल लिए और पानी की रिपोर्ट सही पाई गई। कुछ ऐसा ही हाल वर्तमान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 का है जहां पर फरियादी पर दबाव बनाकर शिकायते वापस ले ली जाती है। पुलिस प्रशासन भी कई फरियादियो पर रिपोर्ट न लिखवाने का दबाव बनाता है। इसी प्रकार अन्य विभाग भी येनकेन प्रकरेण अपनी पीठ थपथपा लेता है। यानी कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में नौकरशाही इतनी हावी है कि, इंदौर जैसे महानगर के महापौर भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और अपनी पीड़ा को कई बार सार्वजनिक भी कर चुके हैं। दूषित पेयजल के मामले में भी महापौर के अनुसार, इसके लिए वे कई बार अधिकारियों को पत्र लिख चुके थे आखिर क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं की गई...? अधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुन रहे हैं... क्या मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है...?

इंदौर के दामन पर लगे इस बदनुमा दाग का जिम्मेदार कौन...? यह तो जांच का विषय है और जांच होगी या नहीं होगी... अगर होगी तो निष्पक्ष होगी...? और दोषियों पर कार्रवाई होगी... यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कल तक जो इंदौरी अपने आप को इंदौरी कहने में गर्व महसूस करता था आज शर्म के मारे अपना सिर झुका रहा है... इंदौर मध्यप्रदेश ही नहीं देश का भी ताज था और ताज पर लगा यह दाग लंबे समय तक दर्द देता रहेगा।

प्रशासन सच को स्वीकारे

दूषित पेयजल के मामले में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका दुख समझ पाना अन्य के लिए कठिन है लेकिन प्रशासन अपनी हठधर्मिता को छोड़कर सच को स्वीकारने का साहस दिखाएं। मृतको की संख्या के मामले में मीडिया की खबरें और सरकारी आंकड़े में दिखाई दे रहा अंतर यह साबित कर रहा है कि, इस संवेदनशील मसले में भी प्रशासन अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है और सच को नकार रहा है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि, वे सही आंकड़ा बनाए और जो मरीज जीवित और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराय ताकि वे शीघ्र स्वस्थ होकर अपने परिजनों के पास जा सके।

अनावश्यक बयानबाजी से बचे नेता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में डबल इंजन की सरकार के लिए मत याचना करते आए हैं। लेकिन इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि है। ऐसे में अगर कोई घटना घटित होती है तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि स्वच्छता में मिले पुरस्कार की वाहवाही भी सभी ने मिलकर ली थी। ऐसी घटनाओं में संवेदनशीलता को देखते हुए अनावश्यक बयानबाजी से जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बचना चाहिए एक गलती सौ अच्छे कामों पर भारी पड़ जाती है। इंदौर की घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि, जिस इंदौर ने जनप्रतिनिधि के रूप में जिसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई एक झटके में अर्श से फर्श पर लाने में जनता देर नहीं करती है। वहीं विपक्षी नेताओं को भी चाहिए कि, राजनीति बाद में होती रहेगी पहली प्राथमिकता मरीजों को सही उपचार मिले यह होना चाहिए। घटना की जिम्मेदारी तो बाद में तय होती रहेगी पहले राजनेता एक अच्छे इंसान होने का परिचय दें और पीड़ितों की हर संभव मदद करने का प्रयास करें। वहीं प्रशासन भी मानवता का परिचय दे और अगर कहीं शिकायत मिल रही है तो उस पर तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करें न की टालमटोल। इंदौर की घटना से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी शहरों और कस्बो में पेयजल स्त्रोतों की जांच प्रारंभ कर दी है लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों की प्रतीक्षा क्यों...?

पेयजल स्त्रोतों की जांच नियमित अंतराल में तय की जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों को यह कार्य अपना कर्तव्य ही नहीं मानव सेवा मानकर पूरी ईमानदारी के साथ नियमित रूप से करना ही चाहिए ताकि इंदौर जैसी घटना की कहीं भी पुनरावृत्ति न हो।

रविवार को भी पेश हो सकता है केंद्रीय बजट

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार का बजट कई दृष्टियों से ऐतिहासिक और विशिष्ट माना जा रहा है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद उसी दिन संसद में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हाल के वर्षों में यह पहला अवसर होगा जब साप्ताहिक अवकाश के दिन बजट के लिए संसदीय कार्यवाही आयोजित की जा सकती है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होने की संभावना है। परंपरा के अनुसार वर्ष 2017 से केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे बजट प्रस्तुत करती आ रही है। इससे पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्यदिवस पर प्रस्तुत किया जाता था, जिसे बाद में बदला गया।

इस वर्ष 1 फरवरी को रविवार होने के साथ-साथ गुरु रविदास जयंती भी है। सामान्य परिस्थितियों में रविवार को सरकारी कार्यालय और शेयर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट के महत्व को देखते हुए सरकार इस परंपरा को बनाए रखने के संकेत दे रही है। इससे पहले भी विशेष परिस्थितियों में शनिवार को बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्ष 2025 में 1 फरवरी शनिवार को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। वहीं, वर्ष 1999 में भी शनिवार को बजट पेश किया गया था, जब बजट प्रस्तुति का समय सायं पांच बजे से बदलकर पूर्वाह्न 11 बजे किया गया था।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को संसद के पटल पर रखा जा सकता है। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को अवकाश रहेगा और 1 फरवरी को मुख्य बजट भाषण होने की संभावना है। बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें पहला चरण लगभग तीन सप्ताह और दूसरा चरण चार सप्ताह तक चलने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति के अभिभाषण का मुख्य विषय सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन रहने की संभावना है, जिसके आधार पर विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में बदलाव और बढ़ते आयात शुल्क जैसी चुनौतियां सामने हैं।

इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की विकास दर को स्थिर और तेज बनाए रखना है। बजट की मुख्य थीम विकसित भारत के लक्ष्य पर आधारित होगी। सरकार का प्रयास औपनिवेशिक सोच के अवशेषों को समाप्त कर भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित पांच संकल्पों की झलक भी इस बजट में दिखाई देने की संभावना है।

हालांकि रविवार को बजट प्रस्तुत करने का अंतिम निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाएगा, लेकिन सरकार के रुख से संकेत मिल रहे हैं कि 1 फरवरी की तिथि से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मेधावी उम्मीदवारों के लिए खुला सामान्य वर्ग

नई दिल्ली, एजेंसी।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि, अनारक्षित अथवा सामान्य वर्ग किसी विशेष समुदाय के लिए सुरक्षित कोटा नहीं है। बल्कि यह पूर्णतः योग्यता आधारित एक खुला मंच है। इस निर्णय से भविष्य की सभी सरकारी भर्तियों की दिशा तय होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी बिना किसी प्रकार की आयु सीमा में छूट या अन्य रियायत का लाभ लिए सामान्य वर्ग के न्यूनतम चयन अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसका चयन अनिवार्य रूप से सामान्य वर्ग की सूची में ही किया जाएगा। न्यायालय ने इसे संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों के अनुरूप बताया है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवाओं में खुला वर्ग का मूल उद्देश्य यही है कि, वहाँ जाति या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव न हो। चयन की एकमात्र कसौटी उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि किसी अभ्यर्थी की आरक्षित पृष्ठभूमि उसे सामान्य सूची में स्थान पाने से नहीं रोक सकती।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग से अधिक हो जाएँ, तब भी योग्य उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीट से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। प्रशासन द्वारा यह तर्क दिया जाता रहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का सामान्य सीट पर चयन उसे दोहरा लाभ देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि योग्यता के आधार पर प्राप्त सफलता को किसी भी स्थिति में अतिरिक्त लाभ नहीं कहा जा सकता। यदि मेधावी उम्मीदवारों को केवल उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित कर दिया गया, तो यह प्रतिभा के साथ अन्याय होगा और समान अवसर की भावना को गहरी ठेस पहुँचेगी। आवेदन पत्र में जाति का उल्लेख केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए होता है, न कि योग्यता के आधार पर मिलने वाले अधिकार को समाप्त करने के लिए।

यह महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टता राजस्थान में न्यायिक सहायकों और लिपिकों की भर्ती से जुड़े विवाद के बाद सामने आई है। इस प्रकरण में अनेक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उन्हें चयन से बाहर कर दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम मुहर लगने से यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव होंगे। एक ओर सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र होगी, वहीं दूसरी ओर वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए सफलता के नए अवसर खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सरकारी चयन प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता की एक मजबूत नींव रखता है, जहाँ अब मेधा को जातिगत सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकेगा।

जी राम जी योजना पर अखिलेश यादव का तीखा हमला

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'जी राम जी योजना' को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की एक सुनियोजित और गोपनीय साजिश है।

बुधवार को अखिलेश यादव ने सामाजिक माध्यम मंच एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केवल नाम बदल देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार मनरेगा का नाम बदलने की आड़ में गरीबों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

सपा प्रमुख ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार लगातार मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को समय पर उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, जिससे पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए नई योजनाओं का भार उठाना कठिन हो गया है। ऐसे हालात में राज्य सरकारें मजबूरीवश मनरेगा जैसी योजनाओं से दूरी बनाएंगी और यह योजना धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी।

अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सैकड़ों ग्राम सभाओं को शहरी श्रेणी में शामिल कर उनका मनरेगा बजट समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा मनरेगा को सशक्त बनाने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त करने की है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा अपने अलावा किसी और का पेट भरते हुए नहीं देख सकती और गरीबों का कल्याण उसके एजेंडे में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब आज भी वही है, लेकिन भाजपा को उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत जी राम जी, गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था।

जी (जय) राम जी की बोलना पड़ेगा...

माही की गूंज, झाबुआ।

मुजम्मिल मंसुरी

केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना जो कि आगे चलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा बनी। उसके बदले विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एन्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी रामजी योजना लागू की है। सरकार का दावा है कि, इससे मनरेगा की कमियों को सुधारा गया है और 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यही नहीं इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री के विजन 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा करने का दावा भी किया जा रहा हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि, इस योजना से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम हटाना एक सुनियोजित साजिश है और राष्ट्रपिता के नाम का अपमान किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस के इस तर्ज को खारिज कर दिया और नई योजना का बिल संसद में पास कर दिया हैं। अब यह योजना जी जी राम जी योजना के नाम से जानी जाएगी।

योजना में पारदर्शिता जरूरी

सरकार ने इस योजना के नाम में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर साधारण बोलचाल वाली भाषा जय राम जी की से भले ही मिला दिया है लेकिन योजना को लागू करने में पारदर्शिता की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मनरेगा में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, कई कामों को कई बार करना दिखाया गया, मजदूरों के स्थान पर मशीनों से कार्य करवाया गया, फर्जी हाजिरी व बिल बनाकर पैसे निकाले गए आदि कई फर्जी कार्य किए गए। जिससे इस योजना में भारी भ्रष्टाचार के चलते इसमें बदलाव जरूरी था। अब सवाल यह उठता है कि, पिछले 11 वर्षों में केंद्र में सरकार किसकी थी और अगर इस योजना में भ्रष्टाचार हो रहा था तो भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी...? और अगर सरकार मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई तो इसकी क्या गारंटी की वीबी जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा...?

बहरहाल सरकार ने इस योजना का नाम तो बदल दिया है जो सामान्य बोलचाल भी भाषा में जय राम जी जो कि, आम आदमी का अभिवादन भी है कहलाएगी। जिसमें सरकार का दावा है कि, इस योजना में मजबूत आजीविका की सुरक्षा है 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी है। विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं जिसमें ग्राम पंचायतो द्वारा पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत सहभागी योजना का निर्माण किया जाएगा। विकास के लिए एकजुट संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण जिसमें विभिन्न योजनाओं के समुचित तालमेल से कन्वर्सेंज, पारदर्शिता की ओर मजबूत कदम जिसमें ग्राम पंचायतो द्वारा साप्ताहिक पब्लिक डिस्फ्लोजर, सुदृढ़ सोशल ऑडिट तंत्र, अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल का निर्माण तथा समग्र ग्रामीण विकास के लिए मूलभूत परिसंपत्तियों का निर्माण जिसमें जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा। मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना होगी सदृढ़, आजीविका के अवसरों का होगा विस्तार तथा प्रतिकूल मौसमिय घटनाओं से बचाव की तैयारी संबंधी कार्यों को किया जाएगा। यह योजना कितनी सफल हो पाएगी यह तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन अब आम नागरिकों को अभिवादन के अलावा जय (जी) राम जी की बोलना पड़ेगा।

अतिथि भर्ती में मनमानीः सूचना अधिकार में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

50 से कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षको को दे दी नियुक्ति...!

माही की गूंज , पेटलावद।
राकेश गेहलोत

पेटलावद ब्लॉक में हुई अतिथि शिक्षक भर्ती में धांधली के समाचार प्रकाशित कर चुके हैं आज फिर हम पेटलावद ब्लॉक के सारंगी संकुल में अतिथि शिक्षक भर्ती के नाम पर कि गई अनियमित्ता का खुलासा सूचना अधिकार में मांगी जानकारी के आधार पर हम कर रहे है, जहा चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे। नियमित शिक्षकों के विरुद्ध होने वाली अतिथि शिक्षको की भर्ती के लिए वही नियम हैं जो नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए है। जिसमें वर्ग तीन के लिए 50 प्रतिशत अंक ओर डीएड की आवश्यकता होती है। सारंगी संकुल में हुई भर्ती को लेकर एक खुलासा शिकायत के आधार पर पूर्व में ही किया गया था कि किस तरह अलग-अलग नियमों से सारंगी संकुल में भर्ती प्रक्रिया की गई। यहां सबसे पहले सारंगी संकुल के माध्यमिक विद्यालय बड़ा मोहनपुरा का मामला सामने आया है जहां की बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां अतिथि पद पर पदस्थ रंजना कुंवर राठौर जिनका स्कोर मात्र 37 है जो वर्ग दो सामाजिक अध्ययन विषय पर पूर्व से कार्य कर रही हैं और वर्तमान में भी नियुक्त है। जबकि वर्तमान में नए खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार पात्र उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित कर प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस संबध में जिम्मेदारो से सवाल पूछे तो नियमों को हटा कर एक ही ज़बाब देते है कि, स्कूल की पालक शिक्षक संघ समिति के प्रस्ताव के आधार पर नियुक्तिया की गई है या उक्त पद के लिए एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है,ऐसे ज़बाब दिए जाते है। शासन के नियम हैं कि, वर्ग दो के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डीएड या बीएड योग्यताधारी पात्र हैं। तो फिर इतनी अंधेरगर्दी कैसे की मात्र 37 प्रतिशत अंक वाले शिक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की होगी... ! उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता हैं। जहा एक-एक पद के लिए दसों आवेदन किए गए वहा एक पद के लिए एक ही आवेदन आना... ! अपने आप में शंका पैदा करता हैं। कोई योग्य उम्मीदवार हमे मिला ही नहीं इसी प्रकार पूरे सारंगी संकुल में अतिथि वर्ग दो में देखे तो कई अपात्र लोग नियुक्ति पा गए हैं जिसमें मा.वी. कर्मदी खेड़ा में गणेश भूरिया 61 तो जालूसीह मेड़ा 55 का स्कोर कार्ड,मा.वि. बोड़ायता में ज्योति गुर्जर 60 , मा.वि. बाछीखेड़ा में लक्ष्मी भूरिया 56,कन्या हाई स्कूल सारंगी में महेश भाभर 87 स्कोर अंकों के साथ कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त अभ्यर्थी जो की शासन के नियमानुसार प्रशिक्षित भी नहीं है। जबकि विकास खंड के लिए अतिथि शिक्षको के लिए जारी विज्ञप्ति में प्रशिक्षित होने के नियम रखे गए थे जिसके आधार पर कई स्कूलों में वर्षों से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। वहीं वर्ग तीन की बात करे तो शासन के नियमानुसार 50 प्रतिशत अंकों के साथ डीएड होना अनिवार्य है। सारंगी संकुल में हाई स्कूल कसार बर्डी मे दिनेश डामर 64, निवेश वर्मा 69 ,मा.वि. कर्मदी खेड़ा में जगदीश गणावा मात्र 48, मा.वि. बोड़ायता में आराधना पाटीदार 67, प्रा.वि.गामड़ी में ललिता मावी मात्र 51 स्कोर कार्ड पर नियुक्ति पा चुके हैं। उपरोक्त अतिथि भी शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। चौंकाने वाली बात ये भी हैं कि, क्या इन पदों के लिए अन्य लोगों ने कोई आवेदन नहीं किए ओर किए तो पूर्व से कार्यरत होने के चलते कम स्कोरकार्ड ओर अप्रशिक्षित होने के बाद भी उन्हीं को अवसर दिया गया, अगर ऐसा किया भी गया तो संकुल के दूसरे स्कूलों में अलग नियम क्यों रखा गया।

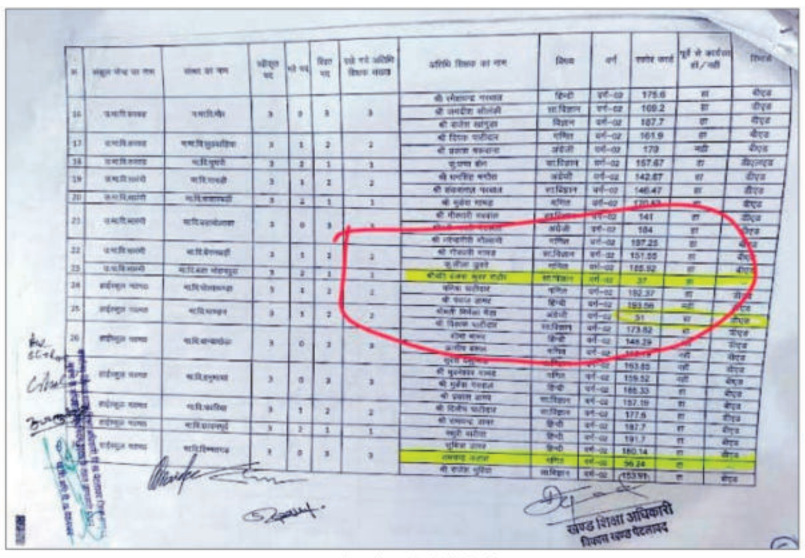
मात्र 37 के स्कोरकार्ड वाले को नियुक्ति!

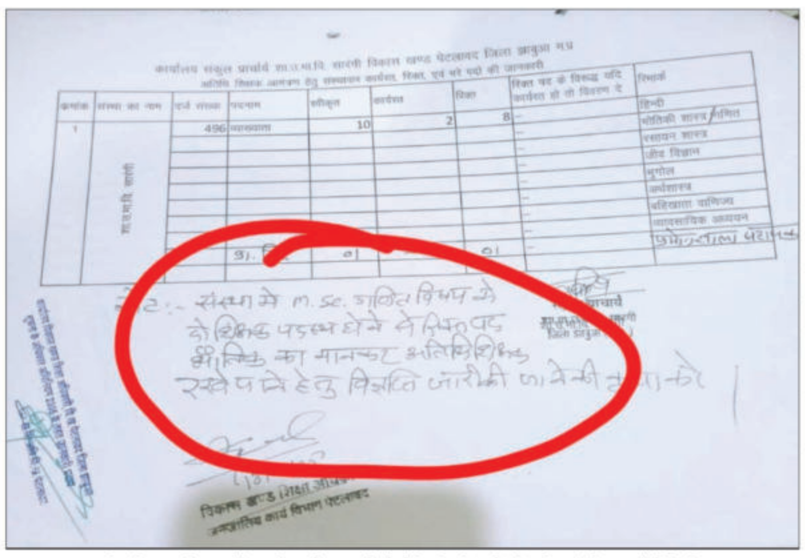
गणित विषय पर शिक्षक होने का नोट जारी कर जारी की थी विज्ञप्ति , फिर भी गणित विषय के शिक्षक को दी नियुक्ति!

जिसे खराब परिणाम के लिए अपात्र किया उसे दी नियुक्ति तो कम स्कोरकार्ड वाले को अधिक स्कोरकार्ड को पात्रता दी

इसके साथ ही वर्ग एक में भी उक्त संकुल में गड़बड़ी की गई है जिसमें उच्चतर मा.वि. सारंगी में वाणिज्य विषय वर्ग एक पर भी नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें नियुक्ति सूची जारी करने के समय नए को नियुक्ति दी गई और पुरानी कार्यरत अतिथि शिक्षिका ममता चौधरी को खराब रिजल्ट का हवाला देकर बाहर किया गया था। परंतु एक नए अतिथि आनंद द्वारा पदभार ग्रहण ना करने की स्थिति में पुनः ख़राब परीक्षा परिणाम देने वाली ममता चौधरी को पुनः नियुक्ति दे दी गई। उससे भी चौंकाने वाला मामला उमावि सारंगी में आया जहा लालचंद अमलियार ओर मांगीलाल गणावा ने वर्ग एक के लिए आवेदन किया था , लालचंद का स्कोर कार्ड 154 ओर मांगीलाल का स्कोर कार्ड 167.9 था लेकिन कम स्कोरकार्ड के बाद भी प्राथमिकता लालचंद को दी गई लेकिन अन्य संस्था में नियुक्ति होने के चलते उमावि सारंगी में नियुक्ति नहीं ली। जिसके बाद अधिक स्कोरकार्ड वाले मांगीलाल गणावा को नियुक्त दी गई।

संकुल के पूर्व संकुल प्राचार्य हिरजी निनामा से इस संबध में बात की उन्होंने बताया कि, भौतिक शास्त्र पर विज्ञप्ति आमंत्रित की थी लेकिन जिन शिक्षकों का चयन हुआ उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया उसके चलते गणित विषय वाले शिक्षक को मौका दिया। प्राचार्य के अनुसार वो सही है लेकिन वर्ग एक के लिए विषय विषेशज्ञ होना आवश्यक है और संकुल की ओर से जारी विज्ञप्ति में गणित विषय के शिक्षक की आवश्यकता नहीं होने का नोट भी जारी किया गया था। बावजूद इसके भौतिक शास्त्र जैसे विषय के लिए गणित के व्याख्याता को लिया गया। इस प्रकार पूरे तालाब में भांग घुली हुई प्रतीत होती। कुल मिलाकर अतिथि शिक्षक भर्ती में चांदी काटी गई होगी। अधिकतर अतिथि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है। लगातार इस प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर प्रशासन को चाहिए कि, इन दोनों स्थानों पर हुई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जाँच करे।

हिंदू संगमःआदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं पर दिया जोर

माही की गूंज, सागवा। परवेश चौहान

खवासा के समीप सागवा मे रविवार को हिंदू संगम का कार्यक्रम आयोजीत किया गया। जिसमें क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप में गौशाला तेजपुर दाहोद के महंत मंगलेश्वर महाराज मंचासीन रहे हैं। विशेष अतिथि के रूप में नीतू बसेर निवासी बामनिया रही। विभाग की सामर्थ टोली की सदस्यता ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बाल कार्यकरणी प्रमुख प्रवीण बैरागी उपस्थित रहे। महंत मंगलेश्वर महाराज ने उदबोधन में कहा कि, वर्तमान समय में जनजाति समाज अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रतीक सजक रहे। उन्होंने कहा कि, जनजाति समाज सदैव सनातन धर्म के लिए सार्थक और सच्चा पूजारी रहा है। प्रभु राम के समय से लेकर देश की आजादी और वर्तमान तक जनजाति समाज ने हर दौर में अपनी आस्था, परंपरा और मातृभूमि के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि, आज कुछ बाहरी संगठन लालच और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके खिलाफ जनजाति समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और रीति रिवाज के प्रति सतर्क रहना होगा। साथ ही आने वाले पीडियो को भी इन मूल्यों से जोड़ना समाज की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सामर्थ, सामाजिक सद्भावना, संस्कृति व जागरूकता का संदेश दिया। लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। हिंदू संगम में न केवल संस्कृति चेतना जागी बल्कि स्थानीय जनजाति समाज के ग्रामीणों में सांस्कृतिक, एकता और परंपरा संरक्षण का भी संदेश मजबूती से दिया गया।

सारंगी मण्डल में हुआ हिंदू संगम

माही की गूंज, सारंगी।

सारंगी मण्डल में रविवार को आयोजित हिंदू संगम उत्साह और सामाजिक एकता के वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की मातृशक्ति, युवा एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जो गंगा जलिया कुएं से प्रारंभ होकर लक्ष्मीनारायण मंदिर तक निकली।

इसके उपरांत छात्रावास मैदान में आयोजित सभा में संत, मातृशक्ति एवं संघ की और से आए वक्ताओं में दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका शिल्पा वर्मा , संत समाज से गढ़ावदिया धाम के श्री श्रीधर जी वैरागी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रतलाम विभाग के जनजातीय विभाग प्रमुख राजेश डावर ने समाज को मार्गदर्शन दिया। वक्ताओं ने हिंदू समाज को एकजुट रहने, अपनी संस्कृति व परंपराओं की रक्षा करने तथा सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। धर्मसभा में राष्ट्र, धर्म और समाज की उन्नति पर विस्तृत विचार रखे गए। वक्ताओं ने कहा कि, ऐसे आयोजन समाज में चेतना, आत्मगौरव और संगठन शक्ति को सुदृढ़ करते हैं।

पेटलावद में भी सामने आया लुटेरी दुल्हन का मामला

कर्नाटक राज्य की लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार

माही की गूंज ,पेटलावद।

शादी के नाम धोखाधड़ी और पत्नी दिलवाने के नाम पर वसूली के कई मामले सामने आते है। इस प्रकार के मामलो में ठगी करने वाली गैंग भी होती हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए शादी करवाने के नाम पर पहले तो वर पक्ष से बड़ी वसूली करते है बाद में दिलवाई हुई दुल्हन भी उस घर पर हाथ साफ कर कुछ समय में ही नो दो ग्यारह होकर निकल जाती है।नगर में ऐसा ही एक मामला सामने जहां लुटेरी दुल्हन व पुलिस ने वैवाहिक धोखाधड़ी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कर्नाटक की एक 'लुटेरी दुल्हन' को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने फरियादी से 4.50 लाख ठगकर फर्जी तरीके से शादी रचाई थी।

आवेदक देवेंद्र राठौर निवासी पेटलावद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मंजू और गीता के माध्यम से उसकी शादी नागवा (निवासी धारवाड़, कर्नाटक) के साथ 18 नवंबर 2025 को संपन्न हुई थी। इसके बदले में आरोपियों ने 4.50 लाख की वसूली की थी। शादी के कुछ दिनों बाद दुल्हन जमीन विवाद का बहाना बनाकर कर्नाटक गई। दुल्हन के जाने के बाद आवेदक को एक व्यक्ति का फोन आया, जिससे पता चला कि नागवा पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, उसने आवेदक के बाद कर्नाटक में एक और व्यक्ति से भी शादी कर ली। वह अन्य साथियों के साथ मिलकर गिरोह चलाती है। पुलिस ने आवेदक की शिकायत पर धारा 318(4), 3(5) ठछै के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीया नागवा को गिरफ्तार कर लिया गया हैद्य थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही हैं जिसके आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी।

भोपाल से अटका क्षेत्र का विकास, जर्जर सड़क के भरोसे क्षेत्रवासी

माही की गूंज,बरवेट।
जगदीश प्रजापत

बरवेट क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़क रायपुरिया बरवेट सारंगी करवड़ 24 किलोमीटर मार्ग चौड़ीकरण का निर्माण कार्य टेंडर सेंशन नही होने के कारण पिछले दो माह से भोपाल अटका पड़ा है। इस सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ नही होने से सड़क मार्ग की हालत खस्ता हो गई है। जिससे इस मार्ग पर सफर करने वालो के साथ साथ आम जन भी परेशान है। टेंडर ओपन होने के चार माह बाद भी इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नही हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नई सड़क के निर्माण के चक्कर में बरसात के बाद इसकी मरम्मत नही हुई जिससे यह मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इधर पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि, टेंडर सेंशन की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

बता दे कि, इस 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण 52 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिस निर्माण कंपनी को ठेका दिया गया है, वो एजेंसी अपनी तैयारी के साथ निर्माण के लिए तैयार है। इधर विभाग का कहना है कि टेंडर सेंशन लेटर मिलते ही ठेकेदार को वर्क आर्डर देकर शीघ्र ही काम शुरू करा दिया जाएगा।

सड़क बनने से राहगीरों की होगी राह आसान

रायपुरिया करवड़ 24 किलोमीटर मार्ग सकरा होने के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। साथ ही रिहायशी इलाकों में वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उड़ने लगते थे। जिसके कारण इन मार्गों के आसपास बने हुए घरों में मिट्टी भर जाती थी। साथ ही छोटे वाहन चालकों को सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते थे और एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इस सड़क मार्ग का चोड़ीकारण बन जाने के बाद इस मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों की राह आसान हो जाएगी।राजकुमार मीणा मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने बताया कि रायपुरिया बरवेट सारंगी करवड़ 24 किलोमीटर मार्ग के चौड़ी करण निर्माण के लिए सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। इस मार्ग के निर्माण कार्य के लिए भोपाल से टेंडर सेंशन की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

रोड पूरी तरह उखड़ चुका है,वाहन चालक और रहवासी हो रहे परेशान।

इंदौर की घटना के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, नगर में कई स्थानों पर नलों से सप्लाई हो रहा दूषित पानी

चार वर्ष बाद भी आरो पाइप लाइन की टेस्टिंग तक नहीं हुई

माही की गूंज, पेटलावद।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतो के बाद कई क्षेत्रों से नल जल योजना के माध्यम से दूषित पानी मिलने की खबरे आ रही है। यहां नगर परिषद पेटलावद में भी नल जल योजना की स्थिति को लेकर अब परिषद के पार्षद ही मुखर होते दिख रहे है ओर इंदौर की घटना के बाद डरने लगे हैं कि, कही इंदौर जैसी स्थिति यहां नहीं बन जाए। जो काम अब तक सरकारी फाइलों ओर परिषद की बैठकों में दबा हुआ था वो अब खुल कर सामने आ गया। यहां वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद हंसा शिवा राठौर के प्रतिनिधि शिवा राठौर ने नल जल योजना से मिल रहे दूषित पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब इस की जांच के लिए वार्ड नंबर 14 की रंगरेज गली में पहुंचे तो पता लगा वार्ड वासियों को मिल रहे पानी की स्थिति बेहत ही चिंताजनक है और पानी पीने के योग्य तो दूर की बात घरेलू कार्य तक के उपयोग के लिए ठीक नहीं है।

इस तरह से दूषित पानी मिल रहा वार्ड क्रमांक 14 के रहवासियों को।

आरो वाटर की लाईन डलने के बाद से है बंद, नई लाइन हो चुकी हैं जर्जर।

आरो वाटर बन कर रह गया सपना, लाइन टेसिंटग तक नहीं हुई

कहने को पूरे नगर में करोड़ो की लागत से आरो वाटर पाइप लाइन बिछाई गई हैं और दावा किया जा रहा है कि, पूरे नगर को आरो वाटर दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में नगर के कई वार्ड ओर वार्ड के कई क्षेत्र में आरो पानी मिलना तो दूर पानी के लिए बिछाई गई नई लाइन तक शुरू नहीं हो पाई है।

वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद प्रतिनिधि शिवा राठौर ने बताया कि, वर्ष 2021 से वार्ड में आरो की ठेकेदार द्वारा लाइन बिछाई गई थी लेकिन ये लाइन अब तक शुरू नहीं हो पाई है। यहां तक कि लाइन की टेसि्ंटग तक नहीं हुई है। वार्ड के लोगों को अब भी पुरानी लाइन से ही पानी मिल रहा है। पार्षद हंसा राठौर ने बताया कि, इंदौर की घटना के बाद वार्ड में भय का माहौल है और गंदे पानी को लेकर वार्डवासी लगातार शिकायत कर रहे है। जबकि मेरे द्वारा पार्षद बनने के बाद से कई बार नगर परिषद की बैठकों में इस विषय को गंभीरता से उठाया लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पार्षद ने ये भी बताया, पुरानी लाइन से नगर परिषद पानी सप्लाई तो कर रही है लेकिन कई घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। नल में सीधे मोटर लगाने के बाद भी कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद दिनेश पडियार से संपर्क करने पर पता चला कि वार्ड नंबर 4 में नई आरो लाइन तो टेसि्ंटग हो गई है लेकिन आज भी पानी पुरानी लाइन से ही मिल रहा हैं और नई लाइन शुरू नहीं हो पाई हैं।

सीएमओ के हवाई फायर

एक ओर पानी को लेकर नगर से अलग-अलग जानकारी सामने आ रही है। वही नगर परिषद की सीएमओ आशा मैंड़ा नगर के उन वार्डो में पहुंच कर हवाई फायर करती नजर आई जहां आरो वाटर लाइन के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। साथ ही आरो पानी सप्लाई के प्लांट का भी दौरा कर नगर की नल जल योजना को सुचारू ओर सुरक्षित बताने का प्रयास किया। जबकि नगर में कई वार्डों में योजना की स्थिति दयनीय है। पूर्व में वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद नल जल योजना में लापरवाही और वार्ड में सुचारू व्यवस्था नहीं होने के चलते धरने पर बैठ चुकी हैं। तो कई वार्डों में ठेकेदार की बिछाई लाइन की जगह नगर परिषद की पुरानी व्यवस्था का उपयोग कर पानी पहुंचाया जा रहा है।

सीएमओ आशा मैंड़ा से इस मामले में चर्चा करने का प्रयास किया तो उनके फोन को किसी अन्य व्यक्ति ने रिसीव कर उनके बीमार होने ओर अस्पताल में भर्ती की जानकारी दी।

प्रदर्शन की तैयारी

वार्ड 14 के रहवासियों ने वर्तमान नल जल योजना के माध्यम से मिल रहे दूषित पानी से लेकर नाराज हैं, पार्षद पति शिवा राठौर ने बताया कि, जल्द ही वार्ड की नल जल योजना की नई लाइन शुरू नहीं की जाती और सुचारू रूप से सभी वार्ड वासियों को पानी नही दिया जाता है तो, वार्ड वासियों के साथ नलों से मिल रहा दूषित पानी ले जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रदर्शन कर समस्या को जिला प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा।

पार्षद हंसा शिवा राठौर।

पलवाड़ में हुआ हिंदू सम्मेलन

माही की गूंज, काकनवानी।

काकनवानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चोखवाड़ा में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन चोखवाड़ा, तोरणिया, बावड़ी, पीपला ढेबर आदि गांव के सीमा पर किया गया एवं यह सीमा गुजरात से भी लगी हुई है। आसपास के सभी क्षेत्र के करीब 9 गांव के लोग शामिल हुए।

हिंदू सम्मेलन में राजस्थान के कोटा से पधारे संत जगदीश दासजी महाराज ने धर्मांतरण विषय पर समाज को जागरूक रहने का आह्वान किया। मंदिर व्यवस्थापक रमेश वसुनिया ने आदिवासी संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखने की आवश्यकता बताई। मातृशक्ति मयूरी धानक ने पंच परिवर्तन विषय पर अपने विचार रखते हुए सामाजिक परिवर्तन में मातृशक्ति की भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख शुभम पंवार ने संघ की 100 वर्षों की संघर्षपूर्ण यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, किस प्रकार संघ ने विपरीत परिस्थितियों, आपातकाल, सामाजिक उपेक्षा और संसाधनों के अभाव के बावजूद निरंतर राष्ट्र व समाज सेवा का कार्य किया। संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य किया है। वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा केंद्र, सेवा प्रकल्प, स्वास्थ्य शिविर, संस्कार वर्ग और सामाजिक समरसता के प्रयासों से समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। श्री पंवार ने बताया कि, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, बाढ़, भूकंप जैसी आपात स्थितियों में स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य किया। उन्होंने कहा कि, संघ का उद्देश्य केवल संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सशक्त समाज का निर्माण है। सम्मेलन शांतिपूर्ण एवं सामाजिक समरसता के संदेश के साथ संपन्न हुआ।

भूरिया मध्य प्रदेश अंडर 14 टीम के कोच बने

माही की गूंज,खवासा।

हाई स्कूल चापानेर खेल शिक्षक राकेश भूरिया को मध्य प्रदेश अंडर 14 बालिका खो-खो टीम का कोच बनाया गया है। लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश के सहायक संचालक ने पत्र जारी किया है। जिसमें उन 69 वीं राष्ट्रीय शालेय खो-खो बालक-बालिका प्रतियोगिता पटेल स्टेडियम केकड़ी राजस्थान में 16 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाना है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के शालेय दल का प्री नेशनल कोचिंग कैंप 9 से 13 जनवरी तक सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला द्वारा आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए खिलाड़ियों और कोच की सूची जारी की गई है। झाबुआ जिले से हाई स्कूल चापानेर के खेल शिक्षक राकेश भूरिया को अंडर 14 बालिका खो-खो टीम मध्य प्रदेश का मुख्य कोच बनाया गया है। जो धार में आयोजित कैंप तथा राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम को कोचिंग देंगे तथा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी इस नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों तथा ईस्ट मित्रों ने बधाई प्रेषित की है।

आकस्मिक निरीक्षणः सवाल पर संतोष जनक जवाब नहीं

माही की गूंज, परवलिया।

नीति आयोग के आईएएस सीनियर अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया। जिसमें शिक्षा स्वास्थ एवं महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी का निरीक्षक किया जिसमें सीईओ जनपद पंचायत थांदला एवं बीएमओ थांदला उपस्थित रहे।

जब जनप्रतिनिधियों ने स्कूल में उचित पानी पीने की व्यवस्था एवं उपस्वास्थ केंद्र में किसी भी रोगी का इलाज नहीं किए जाने जैसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएं, तब अधिकारियों ने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। पेयजल की व्यवस्था को लेकर बात करना चाही तो मेडम ने अपनी गाथा सुनाने लगी। गाँव मे नल जल योजना के तहत पानी तो मिलता है लेकिन आज तक वहा फ़िल्टर प्लांट नहीं लगा। वही जब मेडम की कही बातो का वीडियो बनाने पर आपत्ति भी जताई।

नाम परिवर्तन जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं दिनेश पिता श्री मोहनलाल जी पडियार निवासी सिर्वी मोहल्ला पेटलावद जिला झाबुआ मध्यप्रदेश का होकर एदत द्वारा सूचित करता हूं कि, मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम बदल कर दिनेश पडियार कर लिया है। तथा इस संबध में मैरे द्वारा नाम परिवर्तन हेतु शपथ-पत्र भी दिनांक 06/01/2026 को संपादित करवाया गया है। आज के पश्चात समस्त शासकीय दस्तावेज एवं पत्राचार तथा अन्य समस्त प्रयोजन हेतु मैरा नया नाम दिनेश पडियार पिता श्री मोहनलाल जी पडियार निवासी सिर्वी मोहल्ला पेटलावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ मध्यप्रदेश हैं। अतः सूचित हो ।

दिनांक - 06.01.2026

स्थान - पेटलावद

दिनेश पडियार पिता श्री मोहनलाल जी पडियार निवासी सिर्वी मोहल्ला पेटलावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ मध्यप्रदेश।

पत्रकारों पर एफआईआरः समाचार की प्रभावशीलता से विचलित प्रशासन द्वारा पत्रकार पर प्रतिबंध और प्रताड़ना

माही की गूंज, झाबुआ।

सन् 1799 से लगाकर वर्तमान तक शासन, प्रशासन ने भ्रष्टाचार, या लोगों के ऊपर यातनाएं देती शासन की नीतियों पर प्रशासन की गलत कार्रवाई को उजागर कर जनता को जागरुक करते आए कलमकारों को कूचलने के कारगार प्रयास किए। किंतु देश के प्रति निष्ठावान पत्रकार फिर भी अपने समाचार प्रदर्शन से प्रशासन की लचर व्यवस्था को आम जनता के बीच लाने में अपने प्रयासो को सार्थक करता रहता है। इसी तरह वर्तमान में भी चाहे वो संभागीय स्तर स्थान हो या जिला स्तरीर स्थान जहां प्रशासन के विरोध में किसी पत्रकार ने प्रश्न उठाए वहां प्रशासन अपने हथियार सामने करते हुए सम्बंधित पत्रकार के विरोध में पुलिस कार्रवाई के लिए एफआईआर करवा देता है।

लार्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम, अंग्रेजी शासन पर दूसरों के विचारो के प्रभाव को रोकने के लिए लगाया था। जिसमें प्रकाशन से पहले सरकारी जॉच अनिवार्य थी। 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एजम्स ने लाइसेंसी नियमों के तहत प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भारतीय विचार मुर्तरुप ले रहा था। 1857 में करीब 475 समाचार पत्र थे जो अधिकतर प्रांतिय भाषा में थे, देश में समाचार पत्र लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। समाचारो का असर ब्रिटिश अधिकारियों पर होने लगा था, इसी कारण लाइसेंसी आधिनियम बनाकर प्रेस बंद करवा दी गई। विद्वानों के विरोध के बाद फिर अनेक स्थानों पर समाचार पत्र शुरु हुए। परंतु जब समाचारो के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों की आलोचनाएं होने लगी, नागरिक जागरुकता की तरफ कदम बढ़ाने लगे तब लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागु किया और कड़ा प्रतिबंध लगाया जिसका पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। विरोध को देखते हुए अगले लॉर्ड रिपिन को इस एक्ट को निरस्त करना पड़ा। 1910 में भी भारतीय राष्ट्रीय गतिविधियों को दबाने के लिए भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया गया, जिसमें प्रकाशकों से सुरक्षा जमा मांगने और सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के पूर्ण अधिकार दिए गए। देश में स्वतंत्रता के बाद आपातकाल के समय 1975-1977 में प्रेस पर सेंसरशिप और सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इन सभी प्रतिबंधों में मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रवादी भावनाएं और विचारों को फैलने से रोकना, फिर सरकार की नीतियों और प्रशासन की आलोचना पर अंकुश लगाना, और विद्रोह को रोकने के लिए।

वर्तमान में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन द्वारा किसी भी बात को लेकर एफआईआर करवा दी जाती है। कभी कार्य में बाधा तो कभी भ्रामक खबर चलाने के विषय को उल्लेखित करते हुए। अब कार्रवाई के डर से पत्रकारों की वह पेनल जो कॉपी पेस्ट कर अधिकारियों की जी हुजुरी करती है या प्रशासन के पक्ष में बढ़ा-चढ़ा कर समाचार प्रकाशित करते हैं वे भ्रष्टाचार को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो निडर और साहसी होते हैं वे सत्य को सत्य ही दिखाते हैं।

शासन और प्रशासन सत्य की सहनशीलता से परे है, सत्य को सुनने, समझने फिर उसे सुधारने की शक्ति प्रशासन में बची नहीं है, और कुछ बची भी है तो वो दबी-छुपी पड़ी है। क्योंकि प्रशासन अपने ही अहंकार में अपने ही पाले हुए पत्रकारों से अपनी ही पीठ थपथपवा देते हैं। प्रशासन अपनी कमजोरी, या अपने कार्य के किसी भी रुप की बूराई सुनने या देखने का आदी नहीं है। शासन भी यही चाहता है कि, उसकी नीतियों के विरोध में कहीं कोई खबर न लगे, जिसका पूरा-पूरा ध्यान प्रशासन को रखना पड़ता है। सीधी सी बात है शासन और प्रशासन पत्रकारों से चापलूसी चाहता है, जो कलमकार चापलुसी करता रहता है प्रशासन उसका मुंह मीठा करवा देता है और जो साहस से सत्य प्रकाशित करता है प्रशासन उसके विरोध में कार्रवाई के आदेश दे देता है।

अपने अहंकार पर प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार होता है बस शासन की तरफ से उसे कोई फटकार नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार या गलत कार्य प्रणाली के विरोध में निर्भिकता से प्रकाशन होता है तब प्रदेश मुखिया को परेशानी होती है और जब उस परेशानी के कारण जिला स्तर पर कलेक्टर को फटकार लगती है तब कार्य की गलत नीति को या जनता को होने वाली असुविधा को सही करने के बजाय नियमों को भूलकर प्रशासन कलमकार पर आक्रमककारी की तरह आक्रमण कर देती हैं।

बुद्धीजीवियों के अनुसार प्रशासन के इस रवैये का मूल है भ्रष्टाचार, जिसे किसी न किसी माध्यम से पत्रकार, जनता के सामने लाकर रख देता है। शासन और प्रशासन नहीं चाहता कि, विपक्ष की या जनता की नजर पड़े और बंदर बांट में हिस्सों की बड़ोत्तरी हो, या अन्य किसी को भी मेनेज करना पड़े। फिर एक और मुख्य बात शासन और प्रशासन प्रशंसक ही चाहता है आलोचक नहीं। जब कोई भी मामले में असुविधाओं का या भ्रष्ट्राचार को उजागर किया जाएगा तब जनता की जागरुकता बढ़ेगी और उसी जागरुकता को बढ़ने में प्रशासन रुची नहीं रखता क्योंकि, शासन नहीं चाहता और सत्य को प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर एफआईआर करवा देता है।

रिकेश बैरागी

देखा जाए तो प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी एक गांव को चिन्हित किया जाए फिर देश की स्वतंत्रता के पश्चात से वहां कि योजनाएं और योजनाओं में किए गए कार्य की जांच ही यदि करवा दी जाए तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तंत्र सामने आ जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका प्रशासन इस तरह के किसी तंत्र में सम्मिलित हो।

बहरहाल, अहंकार से नहीं स्वाभिमान से सफलता जीवन में समावित होती है। शासन और प्रशासन तो सदैव से चापलुसी चाहता है मगर मुखिया, चाहे जिले का हो या प्रदेश का उसे अपने आस-पास आलोचक भी रखना चाहीए यही नीति और राजनीति का नियम है। पत्रकार को प्रमाणिकता के साथ अपनी प्रतिबद्धता, मर्यादा के साथ लेखनी का प्रयोग करना चाहीए, क्योंकि समाचार सिर्फ समाचार होता है वह सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता।

संपादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ हुई है। अब चाहे

लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफलताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाईटेक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है। इसके अलावा बंदूकों पर लगाम लगाने के लिये कानून की सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास में व्यापक निवेश करने तथा भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से करने होंगे। ऐसे राज्य में जो एक दशक तक चरमपंथ की त्रासदी झेल चुका हो, अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम वक्त की मांग है। राज्य के सत्ताधीशों को चाहिए कि पंजाब द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को गैंगस्टरों, ड्रग माफिया और आतंकवादियों के घातक गठजोड़ का शिकार कदापि नहीं होने दें।

मादुरो पर अमेरिकी हमले का फैंटानिल एंगल

पुष्परंजन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में नशीले कारोबार का सूत्रधार होने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसके मूल में अमेरिकी युवाओं की रगों में जहर घोलने वाले उच्च तीव्रता के फेंटानिल की तस्करी शामिल रही है। कुछ जानकार बताते हैं कि फेंटानिल ही अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फर्स्ट लेडी समेत हिरासत में लेने की सबसे बड़ी वजह रही है। जबकि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी लिप्सा किसी से छिपी नहीं है।

दरअसल, फेंटानिल, धीरे-धीरे दुनियाभर में सुर्खियों में नजर आ रहा है। अटलांटिक के इस पार यह दवा उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका के अनुभवों को देखते हुए यह स्थिति बदलने वाली है। फेंटानिल एक ऐसी समस्या है, जो शायद ही कभी हल होगी। यह ड्रग, हेरोइन से सौ गुना अधिक घातक है। इसके लिए गांजे या अफ़ीम की खेती की ज़रूरत नहीं है। लैब में तैयार फेन्टानिल, एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, जो मॉर्फिन से 50 गुना अधिक असरदार है। इसे मूल रूप से बेल्जियम के रसायनज्ञ पॉल जैन्सन द्वारा संश्लेषित किया गया था। इस दवा का उपयोग बड़ी सर्जरी के लिए होता रहा है, या फिर कैंसर से होने वाले असहनीय दर्द को कम करने में फेंटानिल उपयोगी है।

भले ही रासायनिक रूप से इसका अफीम से कोई संबंध न हो, मगर यह दवा मॉर्फिन और हेरोइन के समान ओपिओइड रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसे 'ओपिओइड' कहा जाता है। हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, ये उन गतिविधियों को बूस्ट करते हैं, जैसे खान-पान का स्वाद लेने, या फिर यौन व्यवहार में। शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ने के कारण ही ओपिओइड की लत लोग लगा लेते हैं। मतलब, दर्द निवारण के लिए निर्मित फेंटानिल, मौज-मस्ती का साधन बन चुका है।

गंभीर चुनौती यह है कि फेंटानिल की लत एक बार लग गई तो उससे छुटकारा मौत के बाद ही मिल पाता है। साल 1960 के दशक से ही फेंटानिल के मूल तत्व में कई बदलाव और सुधार किए गए हैं, जिससे इसके अनेक प्रकार के वेरिएंट तैयार हुए हैं, जिनका शरीर पर अलग-अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, 'कार्फेंटानिल', मॉर्फिन से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। 'कार्फेंटानिल' का उपयोग, उन्मत हाथियों को शांत करने के लिए किया जाता है।

हेरोइन और कोकीन जैसी दवाओं के साथ फेंटानिल को मिलाने से इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। केवल दो मिलीग्राम फेंटानिल एक वयस्क के लिए घातक हो सकता है। फेंटानिल अमेरिका के ओपिओइड संकट का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। सही से देखा जाये, तो हाल ही में यह खबर आई कि पिछले आठ महीनों में ब्रिटेन में फेंटानिल के कारण कम से कम 75 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन, अमेरिका में इस दवा के कारण मरने वालों की संख्या के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, '2024 में ड्रग ओवरडोज़ से 1,07,543 अमेरिकियों की मौत हुई, जिसमें फेंटेनाइल की वजह से 76,000 से ज़्यादा मौतें हुईं। 2025 तक अमेरिका में ड्रग ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की दर दोगुनी से ज़्यादा हो गई, इसका बड़ा कारण फेंटानिल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी।' डेटा एनालिसिस से पता चलता है, कि फेंटानिल की तस्करी में शामिल लोगों में 75 फीसद अमेरिकंस, करप्ट सिस्टम और पुलिस की सांठगांठ से लगे हुए हैं। ड्रग तस्करी में मात्र 25 प्रतिशत प्रवासी संलग्न दिखे। अर्थात्, अपने ही घर में ट्रम्प प्रशासन इसे रोक पाने में नाकारा साबित हुआ है।

भारत में अंडरवर्ल्ड के गिने-चुने सयाने, फेंटानिल को समझ पाए हैं। 2018 में इंदौर में एक अवैध फेंटानिल लैब का भंडाफोड़ हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पता चलता है, कि 'सिनालोआ ड्रग कार्टेल' से जुड़ा एक भारतीय नागरिक शुरू में संगठन को फेंटानिल प्रीकर्सर केमिकल, एनपीपी और एएनपीपी सप्लाई करता था, जिसे कार्टेल से जुड़ा एक चीनी नागरिक फेंटानिल बनाता था और उसे भारत के बरास्ते मैक्सिको भेजता था। दिसंबर, 2018 में, मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने लगभग 100 किलोग्राम 'फेंटानिल प्रीकर्सर एनपीपी' जब्त किया, जिसमें चार भारतीय पकड़े गए। 6 जनवरी, 2025 को न्यूयॉर्क में गुजराती ड्रग तस्कर, भावेश लाठिया को गिरफ्तार किया गया। भावेश, 'रक्सटर केमिकल्स' का संस्थापक और 'एथोस केमिकल्स' का पूर्व निदेशक रहा है। भावेश लाठिया पर आरोप है कि उसने एक प्रीकर्सर केमिकल पर गलत लेबल लगाकर उसे एंटासिड बताया था। कोई पांच महीना पहले, 18 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर एक हेडलाइन नुमायां हुई- 'फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के कारण भारतीय कंपनी के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के अमेरिकी वीज़ा रद्द।' बताया गया, कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के आधार पर कुछ बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडरशिप के वीज़ा रद्द कर दिए हैं।

दरअसल, फेंटानिल से गर्भ-नाल का सम्बद्ध चीन का रहा है। शी चिनफिंग का यह देश, फेंटानिल निर्माण से लेकर दुनियाभर में सप्लाई का नेटवर्क संभाले हुए है, जिसमें ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। मादुरो तो सबसे कमज़ोर मुर्गा है। कार्रवाई दरअसल, चीन पर होनी चाहिए थी। ब्यूनस आयर्स में जी-20 समिट के दौरान, चीनी राष्ट्रपति शी, फेंटानिल को एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में लेबल करने पर सहमत हुए, जिसे व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने एक 'शानदार मानवीय कदम' बताया था। उसके अगले साल घोषणा हुई कि 1 मई, 2019 से, चीन ने आधिकारिक तौर पर फेंटानिल के सभी रूपों को दवाओं की एक श्रेणी के रूप में नियंत्रित किया। इसने उस प्रतिबद्धता को पूरा किया जो राष्ट्रपति शी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। लेकिन, यह केवल दिखाने भर की कवायद थी।

डार्कनेट मार्केट, वेब पर एक कमर्शियल वेबसाइट है, जिसके ज़रिये नशीले पदार्थ, अवैध हथियार, चोरी किया हुआ डेटा, नकली दस्तावेज़ों का लेन-देन होता है। 'सिल्क रोड', जो 2011 में लॉन्च हुआ, एक डार्कनेट मार्केट था, वह बिटकॉइन के शुरुआती यूज़र्स में से कुछ का ठिकाना था। बाद में पता चला 'सिल्क रोड', फेंटानिल के तस्करों के लिए कोड वर्ड है। ऐसे कई सारे कोडवर्ड 'चाइना गर्ल', 'चाइना व्हाइट', 'व्हाइट ड्रैगन' जैसे नामों से डार्कनेट पर नमूदार हुए। इनके पेमेंट बिटकॉइन के ज़रिये होने लगे, जिसने 'ट्रंप मेमेकॉइन' का नुकसान किया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, 'ट्रम्प परिवार की नेट वर्थ लगभग 7.7 बिलियन डॉलर से घटकर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई, जो डिजिटल एसेट्स में गिरावट से जुड़ी है।' कुछ रणनीतिकारों में माना है, कि फेंटानिल प्रोडक्शन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी-आधारित लेन-देन ने 'ट्रंप मेमेकॉइन' का भट्ठा बैठाया है। ट्रम्प केवल खिसियानी बिल्ली नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीधा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर झपट्टा मारा। लेकिन क्या, इससे फेंटानिल की तस्करी रुक जाएगी?

आस्था कोई भी हो मगर इंसान अच्छा हो

विश्वनाथ सचदेव

लगभग दो दशक पुरानी बात होगी। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण संगीतकार खैयाम साहब के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद लौट रहे थे हम। उस कार्यक्रम में जो वे नहीं कह पाये थे, वही सब बता रहे थे वे। मेरी भूमिका तो सिर्फ श्रोता की थी। अचानक वह बोलते-बोलते रुक गये। कार की खिड़की से दायीं ओर देख रहे थे वे। उनके दोनों हाथ जुड़ गये थे। सिर झुक गया था उनका। मैंने देखा हमारी कार मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजर रही थी। 'आपके धर्म में तो मूर्तिपूजा मना है,' मैंने अनायास ही जैसे उनसे पूछ लिया। वे मुस्कुराये, 'आदत है,' उन्होंने कहा। और फिर इसके बाद हम हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर बात करने लग गये थे।

आज जब मैं यह लिख रहा हूं, अचानक मुझे खैयाम की यह बात याद आ गयी। इसके साथ ही एक और बात भी याद आ रही है। मेरी बेटी कान्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है। स्कूल छोड़े उसे दशकों बीत गये। पर अब भी जब वह अपने बचपन के स्कूल के सामने से गुजरती है तो अनायास उसके हाथ 'क्रॉस' बनाने की मुद्रा में हरकत करने लगते हैं। और अपनी बात करूंदृ मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हुए मेरा सर भी, जैसे अपने आप झुक जाता है। और मैं यह भी जानता हूं कि पूजाग?हों के प्रति यह रवैया सिर्फ खैयाम, मेरी बेटी, या मेरा ही नहीं हैदृ हम जैसे न जाने कितने हैं जो ऐसा करते हैं। और यह सब अनायास हो जाता है। लेकिन कैसे?

इस सवाल का जवाब तो यही है कि ऐसा करने के लिए किसी ने हमें कहा नहीं। मैंने अपनी बेटी से यह कभी नहीं कहा कि वह ऐसा किया करे। आप चाहें तो इसे संस्कारों का परिणाम कह सकते हैं। यह तो संभव है कि मैंने बेटी से कभी यह कहा हो कि सब धर्म समान होते हैं, पर मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी उसे समान मानने के लिए भी कहा हो। कम से कम मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव बच्चों पर नहीं डाला गया। मेरे माता-पिता ने भी कभी ऐसा कोई दबाव हम भाई-बहनों पर नहीं डाला।

उस दिन सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजरते हुए खैयाम साहब का अनजाने में ही सिर झुकाना भी किसी दबाव का परिणाम नहीं था। उन्होंने बताया था कि वे न जाने कब से ऐसा करते आ रहे हैं, और यह भी बताया था उन्होंने कि 'पूजाग?ह के सामने सिर झुकाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर धरा गया है।'

सच है, आशीर्वाद का यह अहसास मंदिर, मस्जिद, चर्च, या गुरुद्वारा, सब देते हैं। और सब धर्मों का आदर करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सर्व धर्म समभाव की संस्कृति है हमारी। हमारा धर्म, यानी हिंदू धर्म, हमें यह सिखाता है कि चाहे ईश्वर कहें या खुदा, गॉड कहें या एक ओंकार, अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, पर पहुंचते सभी एक ही जगह हैंदृपहुंचाते सभी एक ही जगह हैं हमें यह

अलग-अलग रास्ते!

जैन धर्म का एक सिद्धांत हैदृ अनेकांत वाद। यह विचार हमें समझाता है कि मैं सही हूं, पर तुम भी सही हो सकते हो। इतनी-सी बात यदि हम समझ लेते हैं तो फिर कोई विवाद बचता ही नहीं है। ईश्वर एक है फिर मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से भिन्न या बेहतर कैसे हो सकता है? बस इतनी-सी बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा अलग-अलग धर्म का होना एक संयोग मात्र है। मैं किसी एक धर्म में विश्वास करने वाले परिवार में पैदा हुआ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे माता-पिता हिंदू थे, इसलिए मैं भी हिंदू हो गया, वे मुसलमान होते तो मैं आरती की जगह नमाज़ पढ़ रहा होता। इस संदर्भ में मेरी कोई भूमिका हो सकती है तो वह यही है कि यदि हिंदू हूं तो अच्छा हिंदू बनूं, मुसलमान हूं तो बेहतर मुसलमान बनूं, ईसाई हूं तो अच्छा ईसाई बनूं। और यह अच्छा होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान यानी वह जो अपनी आस्था में पूरा विश्वास रखने के बावजूद दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें।

यहीं गड़बड़ हो रही है। हम अपनी आस्था की चिंता तो करते हैं पर दूसरे की आस्था को कुछ नहीं समझते। इसी का परिणाम है कि आज पंथ-निरपेक्षता में विश्वास करने वाले हमारे भारत में धर्म के नाम पर आये दिन झगड़े-फसाद होते रहते हैं। हमारा संविधान हर भारतीय को अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक क्रिया-कलाप की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यही नहीं, हमारा संविधान हमें अपनी आस्था अपने धर्म के प्रचार-प्रसार का भी अधिकार देता है। शर्त सिर्फ यह है कि कोई नागरिक अपने अधिकार की सीमाओं को न लांघे। ये सीमाएं भी परिभाषित हैं हमारे संविधान मेंदृ सब नागरिक समान हैं, कोई नागरिक किसी दूसरे को अपने धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए किसी प्रकार का लालच अथवा दबाव काम में नहीं ले सकता। पर अक्सर हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैंदृऔर इसके लिए दोषी दूसरे को ठहराते हैं। धर्म के नाम पर आज जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वे इसी अतिक्रमण का परिणाम हैं।

ऐसे ही अतिक्रमण का उदाहरण इस बार क्रिसमस के अवसर पर दिखा। देश के अलग-अलग हिस्सों में चर्चों पर, ईसाइयों पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। दंगा करने वाले को यह भी स्वीकार नहीं था कि सांताक्लाज की टोपियां बेचकर कोई अपना पेट भरने के लिए कुछ कमा ले। हद तो यह भी हुई कि चर्चों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया! क्रिसमस के आयोजनों के संदर्भ में हुए विवाद और झगड़े हैरान भी करते हैं और दुखी भी। एक ओर तो हमारे प्रधानमंत्री क्रिसमस के अवसर पर चर्च में जाकर ईसाइयों की पूजा-अर्चना में भाग लेते हैं, धार्मिक भाईचारे का संदेश देने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर कुछ कथित धार्मिक संगठन क्रिसमस के रंग में भंग डालने का खुलेआम अपराध करते हैं। ऐसे कुकृत्य के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिन्हें देखकर हर विवेकशील नागरिक को शर्म आ जाये। शर्म आनी चाहिए कहना, ज़्यादा सही होगा।

हमारा भारत, बहुधर्मी है, बहु जातीय और बहुभाषी भी। यह विविधता हमारी विशेषता ही नहीं, हमारी ताकत भी है। इस विविधता पर अभिमान होना चाहिए हमें। पर धर्म के नाम पर जिस तरह एक-दूसरे को नीचा दिखाने या कम भारतीय समझने की गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 'हे ईश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना'। ईश्वर तो क्षमा कर भी देगा, पर हमारी अपनी चेतना जब तक हमें बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, हम सही अर्थों में इंसान नहीं बन सकते। अब हमें तय करना होगा कि हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं या नहीं।

अरावली की परिभाषा में निहित हो संरक्षण का लक्ष्य

प्रो. सुखदेव सिंह

अरावली पहाड़ियां कभी अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ऊंचे वलित पहाड़ों की श्रृंखला थी जो लाखों साल की टूट-फूट और कटाव से घिसकर ऊंची-नीची पहाड़ियों, चोटियों व चट्टानी उभारों की श्रृंखला बन गई हैं। ये पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक हैं, कई कम ऊंची भी हैं जबकि राजस्थान के माउंट आबू पठार पर गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1,722 मीटर ऊंचाई तक है।

हाल ही में अरावली ने पर्यावरण विशेषज्ञों, समाज और मीडिया का ध्यान खींचा जब किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमओइएफसीसी समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानीय तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली शर्त मंजूर करते हुए एक फैसला सुनाया जिससे सड़कों पर विरोध और बयानबाज़ी होने लगी।

2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरावली पहाड़ों की एक समान परिभाषा बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें समुद्र तल के बजाय स्थानीय तल आधारित राजस्थान की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया जा सके। राजस्थान की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, समिति ने मानदंड तैयार किए कि पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा मानने के लिए इसकी ऊंचाई आसपास के स्तर से 100 मीटर होनी चाहिए या इसे अरावली श्रृंखला में दो योग्य पहाड़ियों के बीच 500 मीटर दायरे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को इस परिभाषा को मंजूर कर लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ।

सरकार ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए इसे मात्र 'तकनीकी' स्पष्टीकरण बताया और कहा कि राजस्थान में यह 2006 से लागू है व इससे अरावली की हर जगह एक जैसी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचना के भी यही बिंदु हैं। गत 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक असंतोष का हवाला देकर 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी।

अरावली के लिए टेक्निकल कमेटी द्वारा सुझाई समुद्र तल के बजाय लोकल-एरिया तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली व्याख्या अपने आप में त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक और मनमानी आधारित है, न कि पहाड़ी की ऊंचाई मापने के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक। यह क्षेत्र ऐसे भी समुद्र तल से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, यानी यहां के स्थानीय स्थल से 99 मीटर ऊंचा पहाड़ समुद्र तल से 199 मीटर ऊंचा होगा परन्तु टेक्निकल समिति की व्याख्या अनुसार यह पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जायेगा जब तक

100 मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के 500 मीटर दायरे में नहीं आएगा। इससे राजस्थान के 90 फीसदी पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण मुताबिक, राजस्थान में 12081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड पूरा करेंगी।

समुद्र तल एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज़्ड रेफरेंस पॉइंट है, जबकि लोकल रिलीफ मनमाना है। दूसरा, राजस्थान में एक परिभाषा है और उसी के अनुसार माइनिंग की अनुमति है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं और माइनिंग पर रोक है। कमेटी ने राजस्थान लीगल कोड में अरावली को परिभाषित कर 'एक समानता' जोड़ी व इसे हरियाणा और अरावली रेंज साझा करने वाले सभी राज्यों में लागू किया, जिससे कानूनन हरियाणा में भी माइनिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति की राह खुलती है।

परिभाषा का घोषित लक्ष्य अरावली में माइनिंग को 'रेगुलेट' करना है, न कि रोकना। दिल्ली और हरियाणा में अरावली में ज़्यादा अलग-थलग छोटी पहाड़ियां और चोटियां हैं। यही वह मुख्य बात है जिस पर रियल एस्टेट कारोबारियों की नज़र है, जो गुड़गांव व फरीदाबाद जिलों में अपने कार्य को कानूनी रूप देना चाहते हैं, जहां वे किसी न किसी तरह से पहले ही काम कर रहे हैं, जिससे वहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। साल 2023 के एक सर्वे में, इस इलाके में 786 एकड़ ज़मीन पर मंजूरशुदा इमारतों के अलावा, लग्ज़री फार्म हाउस, रिसॉर्ट, बैंक्वेट हॉल, घर, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान वगैरह के रूप में 6793 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर पाए गए।

यह बाज़ार-संचालित खनन, वनों की कटाई और रियल एस्टेट विकास है जिससे अरावली पहाड़ियों को खतरा है। एक बार जब अरावली के कुछ हिस्सों को उसके दायरे से बाहर रखने के लिए परिभाषित किया जाएगा, तो खनन और रियल एस्टेट कंपनियों को न उस क्षेत्र पर कानूनन कब्ज़ा करने की अनुमति मिल जाएगी; इसके बाद उन्हें अरावली के दिल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। बाज़ार-संचालित ताकतें इसी तरह काम करती हैं। 'मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने' के मकसद से काम करने वाली बाज़ार-संचालित ताकतें मानवीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और प्राकृतिक चिंताओं के 'बाहरी प्रभावों' पर ध्यान नहीं देतीं, जिसके चलते प्रदूषण, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होता है।

यहीं पर सरकारों को हस्तक्षेप करना होगा और बाज़ार की ताकतों को अपने पक्ष में सब कुछ तय करने देने के बजाय मानव कल्याण, पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए, अरावली पहाड़ियों के लिए एक ऐसी परिभाषा, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकती है, अपनाने और कानून बनाने से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए।

सेवाकुंज परिसर से सीतामऊ साहित्य महोत्सव के द्वितीय संस्करण का भव्य आगाज

माही की गूंज, मंदसौर।

छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर में 29 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव के द्वितीय संस्करण का मंगलवार को लदूना तालाब स्थित सेवाकुंज परिसर से विधिवत एवं भव्य आगाज किया गया। इस अवसर पर 1000 आकाशदीप आकाश में उड़ाए गए तथा आकर्षक आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा सेवाकुंज परिसर प्रकाशमय हो उठा।

साहित्य महोत्सव के इस आगाज कार्यक्रम ने साहित्य, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का सशक्त संदेश दिया। अपनी समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध मंदसौर जिले का सीतामऊ नगर आगामी आयोजन में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा का भव्य प्रदर्शन करेगा। मुख्य आयोजन 29, 30 एवं 31 जनवरी को सीतामऊ में आयोजित होगा, जिसमें साहित्य, कला, संस्कृति एवं दर्शन से जुड़ी देश की जानी-मानी हस्तियां सहभागिता करेंगी। तीन दिवसीय आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न विधाओं से जुड़े रुचिकर और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आगाज कार्यक्रम के दौरान दोपहर में बच्चों के लिए विशेष बाल मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा रचनात्मक एवं आकर्षक स्टॉल लगाए गए। पानीपुरी, फ्रूट चाट, मेहंदी पेंटिंग सहित अनेक मनोरंजक स्टॉल बच्चों द्वारा संचालित किए गए। कलेक्टर अदिती गर्ग ने बाल मेले का अवलोकन कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर कलेक्टर अदिती गर्ग, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह डंग, स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक, विद्यार्थी एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।

साइकिल टकराने से उपजा बड़ा विवाद

माही की गूंज, रतलाम।

शहर में सिटी सराय इलाके में रविवार रात एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 27 वर्षीय जूता व्यापारी फरहानुद्दीन अंसारी पर अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह पूरी घटना उस समय शुरू हुई, जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने फरहानुद्दीन की दुकान के बाहर खड़ी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सड़क पर गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फरहानुद्दीन ने बाइक सवार से केवल इतनी बात कही कि वाहन सावधानी से चलाया करो। इस साधारण सी बात पर बाइक सवार गाली-गलौज करने लगा। इस बीच वहां लोग एकत्र हो गए तो वह युवक वहां से चला गया। जाते-जाते उसने धमकी दी कि वह वापस आएगा, जिसे उस वक्त किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही मिनटों बाद वही युवक दो अन्य साथियों के साथ वापस लौटा और तीनों ने मिलकर फरहानुद्दीन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले थप्पड़ मारे और फिर लात-घूंसे से देर तक पीटते रहे। इस हमले में फरहानुद्दीन के दाहिने हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुई इस मारपीट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। जब मुनव्वर सुल्तान नाम की एक महिला बीच-बचाव करने पहुंची, तो हमलावरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। मारपीट के दौरान महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ितों का कहना है कि जाते-जाते आरोपियों ने फरहानुद्दीन को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद घबराहट में आरोपी अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके पर छोड़ी गई मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अब तक हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

मेयर के बेटे ने जब खोल दी थी भ्रष्टाचार की पोल...!

इंदौर।

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर 'हथियार' की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का तांडव मचा है, वहीं दूसरी तरफ संघमित्र का अपनी ही सरकार की नीतियों पर किया गया तीखा प्रहार अब उनके पिता और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है।

यह वीडियो 4 सितंबर 2025 का है, जब देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसी आयोजन में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे थे। संघमित्र ने बुलेट ट्रेन, वेटिंग लिस्ट और रेलवे के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था।

संघमित्र को बोलते सुना जा सकता है, ''ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाते। वादा था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन सरकार के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए खर्च हुए, घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन हकीकत में नहीं आई। सरकार दावा करती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे रुकेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20 हजार लोग रेल हादसों में मारे गए। जब रेल पटरी से उतरती है, तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद सूनी होती है, बच्चे का भविष्य अंधेरे में डूबता है और बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद छिन जाती है।''

स्कूली छात्र संघमित्र ने आगे कहा, ''स्टेशन रिडेवलपमेंट की बात होती है। सरकार ने कहा था कि 400 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनेंगे, लेकिन सिर्फ 20 बने। वहां भी शिकायतें हैं कि चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ वही है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि स्टेशन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 लाख करोड़ रुपये में से 8Q परियोजनाएं अधूरी हैं. सुरक्षा के लिए 78 बजट डायवर्ट कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग एक ही कंपनी को दे दी गई। सरकार कहती है 'सबका साथ, सबका विकास,' लेकिन रेलवे में हो रहा है दलाल का साथ, निजीकरण का विकास और जनता का विनाश।''

खास बात यह रही इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, स्थानीय बीजेपी विधायक और मेयर पुष्यमित्र मौजूद थे। बीजेपी नेता असहज दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए भाषण सुनते रहे। उधर, साहसिक भाषण पर ऑडिटोरियम में मौजूद श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाईं।

अब यही वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि इंदौर नगर निगम पर आरोप लग रहे हैं कि वहां काम के नाम पर सिर्फ 'पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन' होते रहे, जबकि जमीन पर जनता जहरीला पानी पीती रही।

बता दें कि, इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इस वक्त मातम में डूबा है। दूषित पानी की सप्लाई ने यहां कहर बरपाया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार केवल 6 लोगों की जान गई है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रहवासियों का दावा है कि अब तक 17 लोग दूषित जल के कारण दम तोड़ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। आज किसी का बेटा, किसी की मां तो किसी का पिता इस दुनिया से चला गया।

सोशल मीडिया यूजर्स संघमित्र के वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, ÷बेटा सरकार से सवाल पूछने में माहिर है, काश पिता (मेयर) भी जनता की जान बचाने में इतने ही माहिर होते।÷ लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेयर के घर में भी ऐसा ही पानी आता है जैसा भागीरथपुरा की गरीब जनता को पिलाया गया...?

कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने एफआईआर में लिख दी बाइक

पन्ना।

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक्सीडेंट के बाद बीमा क्लेम से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने सड़क दुर्घटना में शामिल वाहन ही बदल डाला। स्कूटी और कार की टक्कर को बाइक एक्सीडेंट बताकर एफआईआर दर्ज की गई। जब हादसे का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एएसआई को निलंबित कर दिया है।

दरअसल, यह पूरा मामला पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र का है। बीते 10 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजकर 38 मिनट पर धरमपुरा पेट्रोल पंप के पास दुल्लीचंद राठौर और उनकी छोटी बहू प्रिया सिंह का चार पहिया वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद दोनों घायलों को शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से डॉक्टर सर्वेश लोधी ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कटनी रेफर कर दिया। कटनी में दोनों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस दुर्घटना के 9 दिन बाद, यानी 19 दिसंबर 2025 को शाहनगर पुलिस द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज अपराध क्रमांक 439/2025 में वास्तविक चार पहिया वाहन की जगह एक दो पहिया वाहन से दुर्घटना होना दर्शाया गया।

एफआईआर में जिस बाइक को दुर्घटना में शामिल बताया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर (एमपी 20 जेडसी 9890) है, जबकि यह वाहन घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर चार पहिया वाहन से हादसा होते हुए दिखाई दे रहा है।

आरोप है कि शाहनगर थाने में पदस्थ एएसआई रामलखन पयासी द्वारा जानबूझकर तथ्यों में हेरफेर कर दो पहिया वाहन को मामले में शामिल किया गया, ताकि बीमा नियमों का लाभ उठाया जा सके। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा ऐसे मामलों को आय का जरिया बनाया जा रहा था। बीमा क्लेम पास कराने की नीयत से दस्तावेजों और एफआईआर में बदलाव किया गया। यहां तक कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने बचाव में पीड़ित से एफिडेविट और आवेदन भी बनवाया।

मामला सामने आने के बाद पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शाहनगर थाने में पदस्थ एएसआई रामलखन पयासी को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच पवई एसडीओपी भावना दांगी को सौंपी गई है।

इस घटना ने न सिर्फ शाहनगर थाना, बल्कि पूरी पन्ना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि जब मीडिया ने इस मामले में शाहनगर थाना प्रभारी मनोज यादव से बात की, तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। जबकि इस मामले में समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

नाम है अमन, पर फैला रहा था अशांति

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम रेलवे स्टेशन पर हुई चाकूबाजी की घटना ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया। आरोपी अमन ने स्टेशन परिसर में एक यात्री पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद जीआरपी पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चाकू से हमला कर यात्री को किया घायल

दो दिन पहले नीमच से रतलाम आए यात्री सादिक पर आरोपी अमन ने अचानक चाकू से कई वार किए। इस हमले में सादिक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए दो से तीन टीमों का गठन किया। रतलाम की बिलपांक पुलिस और साइबर टीम की मदद से अमन को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वह खटकेदार चाकू भी बरामद कर लिया, जिससे उसने हमला किया था।

आरोपी को जेल भेजा गया

गिरफ्तारी के बाद जीआरपी पुलिस ने अमन को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन स्टेशन परिसर में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

रेलवे स्टेशन पर इस तरह की घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है कि कोई भी आरोपी खुलेआम हमला कर सकता है। यात्रियों का कहना है कि प्रशासन को सुरक्षा इंतजाम और मजबूत करने होंगे।

गांधी सागर की आर्द्रभूमियों में पंखों की गिनती

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले की आर्द्रभूमियां इस सर्दी में पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत नजर आईं। 03 एवं 04 जनवरी 2026 को जिले में प्रथम एशियन वॉटरबर्ड सेंसस का आयोजन किया गया, जिसमें गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य सहित जिले के लगभग 40 प्रमुख वेटलैंड क्षेत्रों में प्रवासी एवं स्थानीय जलपक्षियों की गणना की गई। इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का उद्देश्य पक्षियों की संख्या जानने के साथ उनकी प्रजातीय विविधता और आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक स्थिति को समझना रहा।

वनमंडल अधिकारी संजय रायखेरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेंसस में गांधीसागर अभयारण्य के साथ लदुना तालाब, मल्हाड़गढ़ तालाब, तेलिया तालाब सहित जिले के अन्य प्रमुख जलाशयों को शामिल किया गया। दो दिनों तक चले इस अभ्यास में वैज्ञानिक पद्धति से पक्षियों का अवलोकन, पहचान और गणना की गई। इस सेंसस की खास बात यह रही कि इसमें वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ जिले के स्थानीय पक्षी प्रेमियों, स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) एवं वाइल्ड लाइफ वॉरियर समूह के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह की पहली किरण के साथ दूरबीन और कैमरों से लैस दल जलाशयों के किनारे नजर आए, जहां हर उड़ान, हर आवाज और हर झुंड को बारीकी से दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि गांधीसागर का बैकवाटर क्षेत्र सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। अनुकूल तापमान, भरपूर जल और प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता के कारण दूर-दराज से पक्षी यहां आते हैं। यही वजह है कि सर्दियों के महीनों में यह क्षेत्र जैव विविधता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और इसका पारिस्थितिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

सेंसस के दौरान लगभग 169 प्रजातियों के पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जो जिले की आर्द्रभूमियों की समृद्धि को दर्शाती है। इनमें पेंटेड स्टॉर्क, वूली नेक्ड स्टॉर्क और रूडी शेल्डक जैसे आकर्षक जलपक्षियों के साथ-साथ पेंटेड स्परफ्राउल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, डालमेशियन पेलिकन, ग्रेट थिक-नी, चेस्टनट बेलीड सैंडग्राउज, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, इंडियन ईगल आउल, पल्लिड हैरियर तथा विभिन्न प्रजातियों के गल (सीगल) पक्षी शामिल रहे। इन प्रजातियों की उपस्थिति यह स्पष्ट संकेत देती है कि जिले की आर्द्रभूमियां पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास बनी हुई हैं।

वनमंडल अधिकारी ने बताया कि, इस सेंसस से प्राप्त आंकड़ों को वैश्विक जलपक्षी डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। ये आंकड़े भविष्य में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, आर्द्रभूमि प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रथम एशियन वॉटरबर्ड सेंसस ने न केवल जिले की प्राकृतिक धरोहर को रेखांकित किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि यदि संरक्षण के प्रयास निरंतर जारी रहें, तो गांधीसागर और आसपास की आर्द्रभूमियां आने वाले वर्षों में भी पक्षियों की सुरक्षित शरणस्थली बनी रहेंगी।

संकट में है देश का जल -धन, पर्याप्त प्रबंधन और शुद्धीकरण से परे पेयजल

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रदेशभर में सरकार के आदेश से पेयजल की जांच शुरु की जा चूकी है, जिसे देखकर लगता है सरकार कहावत को साकार कर रही है। कहावत है, जब प्यास लगे तब कुआं खोदे। भ्रष्ट्राचार, लापरवाही, घुसखोरी, का ऐसा आलम कि, इंदौर में दूषित पेयजल से 18 मौत हो गई और इंदौर का भागीरथपुरा महामारी ग्रस्त घोषित कर दिया गया। भागीरथपुरा उसी इंदौर में है जिसने देशभर में स्वच्छता को लेकर बीते आठ वर्षों से स्वयं को नम्बर वन बनाए रखा है। रोगी बढ़ते जा रहे है, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सामान्य से अधिक रोगी मिलने पर उस क्षेत्र को महामारी माना जाता है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बने ड्रेनेज चेम्बरों का सीवेज अंदर ही अंदर रिसकर आसपास के बोरिंग में मिल गया और दुषित पानी से फीकल कोलिफार्म बैक्टीरिया लोगों के शरीर में फैलता गया।

इस घटना के बाद जांच को लेकर अधिकारी अपने अधिनिस्थ की कमर कस कर गठान पर गठान लगा रहे हैं, परंतु सच इससे भी ज्यादा भयावह है। क्योंकि पेयजल को लेकर संबंधित विभाग से लगाकर जिला अधिकारी, कलेक्टर तक पेयजल के लिए लापरवाह है। प्रत्येक जिले में जलस्त्रोत, प्रदूषण के कारण दूषित हो रहे हैं। मुख्यतः प्रदेशभर में 2515 उद्योग ऐसे है जो नदी, झील, तालाब, जलाशय के साथ भूजल को भी दूषित कर रहे हैं। वहीं प्रदूषण बोर्ड की लापरवाही कहे या राजनेताओं की मनमानी प्रदेश में संचालित 5961 उद्योगों ने मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड से समेकित सहमति और प्राधिकरण (कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड अथाराइजेशन, सीसीए) को नवीनीकरण नहीं कराया है। जबकि नेता, अधिकारी सभी को पता है कि, इन उद्योगों से निकलने वाले रसायनयुक्त पानी जलस्त्रोतो में मिलने से आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। प्रदेश में सात हजार अमृत मित्र जल गुणवत्ता पर परीक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत 3.70 करोड़ रुपए का बजट मध्यप्रदेश को दिया गया है, और अमृत मित्र के अंतर्गत 184 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चूकी है। बावजूद इसके मध्यप्रदेश में 305 नदियां तालाब, झीले, और जलाशय प्रदुषित हो रहे हैं।

प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में भी फेक्ट्रियों से निकला रसायनयुक्त जल नदी, नालों, तालाबो में मिलकर जीवन प्रभावित करता है, अनेको बार दूषित पानी पीने से पशुओं की मौत हो जाती है। आस पड़ौस के ग्रामीण

अक्सर बिमार रहते हैं। नेता एक दिन होशियारी में दूषित पानी के विरोध में प्रदर्शन करते हैं उनको सहयोग के तौर पर फैक्ट्री मालिको की तरफ से हां में ईशारा मिल जाता है और उसके बाद से विरोध पूरा हो जाता है। प्रदेश के प्रत्येक स्थान जहां उद्योग लगे हुए है वहां ऐसा ही हो रहा है। वहीं जब रिपोर्ट है कि, प्रदेश के 5961 उद्योगों ने सीसीए नविनीकरण नहीं करवाया है तो प्रदुषण विभाग किस नींद में सो रहा है उसे कार्रवाई करने से किसने रोका है।

स्वच्छता में अव्वल रहे इंदौर में भागीरथपुरा की मौतें देश के लिए दिशा है कि, सरकारें जल की स्वच्छता और उपलब्धता पर सतर्क हो जाए। केंद्र ने शुद्ध पेयजल के लिए दो मिशन शुरु किए अमृत मिशन, और जल जीवन मिशन। मगर राज्य सरकारें दोनों में सक्रीय ना के बराबर ही है।

अमृत मिशन 1.0 में 32 पुराने जल संशोधन संयंत्रो के उन्नयन से जुड़ी परियोजनाओं को सहमति दी। वहीं अमृत मिशन 2.0 में 132 नए जल शोधन संयंत्रों को लगाने की परियोजना स्वीकृत की। परंतु राज्यों का सुस्त रवैया और लापरवाही के कारण 4 परियोजनाएं पूरी हो पाई। इनमें सबसे अधिक 43 जल संशोधन संयंत्रों को लगाने की परियोजनाएं सिर्फ मध्यप्रदेश में स्वीकृत किए गए है। जल जीवन मिशन की हालत भी कोमा में पड़े रोगी की तरह है।

देश में जल संकट बढ़ रहा है, पेयजल का ठीक से प्रबंधन नहीं होने के कारण बहुत सा पानी व्यर्थ ही बह जाता है। जबकि पेयजल की उपलब्धता अर्थात उसके स्त्रोत सिर्फ चार प्रतिशत ही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 20 सबसे अधिक जल संकट ग्रस्त शहर है जिसमें से पांच शहर भारत में ही है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु और हेदराबाद शामिल हैं।

समस्या नई है तो समाधान भी नये निकालने होगे, बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या रोजगार, बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों में आ रही है। लोग शहरों में आकर बिना ले-आउट स्वीकृत कराए, टाऊन एवं कंट्री प्लानींग से अनुमति के बिना ही मकान बना लेते हैं। सीवेज सिस्टम होता नहीं है, होता भी है तो उसमें भ्रष्टाचार का पलिता लग जाता है। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पानी में प्रदूषण है, पेयजल पाईप लाईन बरसो बरस पुरानी है। नदियों, तालाबो में सीवेज का पानी मिल रहा है। पूरे प्रदेश में नागरिको को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकायों अकर्मण्यता कैसे एक स्वच्छ शहर की छवि खराब कर सकती है इंदौर के भागीरथपुरा की दर्दनाक घटना इसका उदाहरण है।

बहरहाल जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी तो ली जाती है। प्रदेश मुखिया ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कर्रवाई करने की बात कही हैं। जिसमें अधिकारियों के स्थानानंतरण कर दिए गए, किसी को निलंबित कर दिया गया। क्या 18 मौतों के जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी है और अगर सिर्फ अधिकारी है तो निलबंन और स्थानानतरण की इतनी सी सजा पर्याप्त है? 18 मौतों के जिम्मेदार क्यो कोई नेता, पार्षद, प्रतिनिधी, विधायक कोई भी नहीं ! इन नेताओं को अपने क्षेत्र की स्थिति नहीं पता थी, या ये सिर्फ और सिर्फ नाम के नेता या जन प्रतिनिधी बने हैं? फीकल कोलिपार्म बैक्टीरिया से हुई मौत कोई सामान्य मौत नहीं, दूषित पानी द्वारा की गई हत्याएं है, और इन हत्याओं का जिम्मेदार हर वो नेता, जन प्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी है जो उस क्षेत्र से संबंध रखता था और उस हर व्यक्ति पर एफआईआर करवाई जाना चाहिए।

तेंदुए के हमले के बाद लोगों में भय

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पांचाल

काकनवानी के समीपस्त मोरझरी ग्राम में चार रोज पहले एक गेहूं के खेत में तेंदुआ देखा गया जहां बच्चे खेल रहे थे। जिन्होंने चिल्लाकर ग्राम वासियों को एकत्रित किया। सभी ग्राम वासियों ने मिलकर उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जिसके बाद तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे चार-पांच लोग घायल भी हो गए। वन विभाग द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर तेंदुआ की पकडे जाने की खबर फैलाई गई जो कि गलत है। वन विभाग के अधिकारी के अनुसार तेंदुआ गांव में देखा गया था जो की एक आम के वृक्ष पर चढ़ गया था लेकिन वह पकड़ में नहीं आया, शायद जंगल की ओर निकल गया है।

वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अभी भी लगातार ड्रोन द्वारा देखा जा रहा है लेकिन कहीं भी आसपास तेंदुए के पेर के निशान भी नहीं मिल रहे हैं। लगातार सर्चिंग करने पर लक्कड़भग्गे के पांव के निशान देखे गए हैं लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है।

466 करोड़ खर्च, फिर भी खेत सूखे

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिले की जावर उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर संयुक्त किसान संगठन ने बड़े पैमाने पर घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। किसानों का आरोप है कि 466 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद 26 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य केवल कागजों में ही पूरा दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में अधिकांश खेत आज भी सूखे पड़े हैं।

संयुक्त किसान संगठन का कहना है कि यदि परियोजना पर इतना बड़ा खर्च हो चुका है, तो फिर किसानों के खेतों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा। संगठन ने सवाल उठाया कि जब सरकारी दस्तावेजों में सिंचाई पूरी बताई जा रही है, तो खेतों में आज भी फसलें सूखने को मजबूर क्यों हैं। किसानों ने इसे सिंचाई योजना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण बताया है।

किसानों का आरोप है कि सिंचाई के नाम पर झूठे आंकड़े और फर्जी प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं। हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने का दावा किया गया, लेकिन वास्तव में पानी खेतों तक नहीं पहुंचा। अधूरे और घटिया निर्माण कार्यों को पूर्ण दर्शाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। पंप, पाइपलाइन और अन्य संरचनाएं कागजों में मजबूत दिखाई गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर वे पूरी तरह विफल साबित हो रही हैं।

संगठन ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों की आपसी मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक ओर किसान फसलों के नुकसान से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार लोग परियोजना से लाभ उठा रहे हैं।

संयुक्त किसान संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि जावर उद्वहन सिंचाई परियोजना की उच्चस्तरीय, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए। वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन कराया जाए। दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। किसानों को गुमराह करने वाली झूठी रिपोर्टों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए तथा जब तक खेतों तक वास्तविक रूप से पानी नहीं पहुंचे, तब तक परियोजना को पूर्ण घोषित न किया जाए।

महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

भीकनगांव क्षेत्र में मंगलवार को हुई एक महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। प्रेम संबंध और चरित्र पर संदेह के चलते महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

मृतका की पहचान भीकनगांव के फ्रीगंज क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय महिला के रूप में हुई है। भीकनगांव थाना क्षेत्र के गणपति बेड़ा इलाके में झाड़ियों के पास महिला का शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी।

भीकनगांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। घटनास्थल के निरीक्षण में पाया गया कि मृतका की नाक से खून निकल रहा था और पास में उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई, जिसकी पुष्टि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई। पुलिस ने मृतका के निवास स्थान से घटनास्थल तक के मार्गों पर लगे बंद परिपथ दूरदर्शन कैमरों के दृश्य खंगाले। इन दृश्यों में 4 जनवरी को महिला को भीकनगांव के सराफा बाजार से पैदल जाते हुए देखा गया। जांच में सामने आया कि मृतका का खंडवा जिले के जामली निवासी योगेश, पिता कालू बारे, से प्रेम संबंध था और उसे भी घटनास्थल के आसपास देखा गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी योगेश को पंधाना थाना क्षेत्र के जामली से हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मृतका के चरित्र पर संदेह के कारण उसे घटनास्थल पर बुलाया और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार आरोपी योगेश के विरुद्ध वर्ष 2019 में पंधाना थाने में जान से मारने की धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोप में भी मामला दर्ज है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

आग से झुलसी महिला को पुलिस ने बचाया

माही की गूंज, महेश्वर।

मंडलेश्वर के सोनिया नगर क्षेत्र में भटक रही एक गंभीर रूप से झुलसी और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को पुलिस ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया। महिला को तत्काल मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है तथा उसके परिजनों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को स्थानीय नागरिकों ने एक महिला को संदिग्ध अवस्था में झुलसी हुई हालत में घूमते देखा और इसकी सूचना थाने को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को मौके पर भेजा और महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

पूछताछ में महिला ने अपना नाम टहलका बाई, पति शंकर, निवासी ग्राम बीड़, भगवानपुरा थाना मूंदी, जिला खंडवा बताया। महिला ने बताया कि वह लगभग एक माह पूर्व उज्जैन में थी, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिगरेट जलाने वाले यंत्र से उसके कपड़ों में आग लगा दी थी। इसके बाद उसका उपचार अस्पताल में चल रहा था।

उपनिरीक्षक प्रवीण निकुंम ने बताया कि महिला मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि उपचार के समय घावों की पट्टी बदलने पर उसे अत्यधिक पीड़ा होती थी। इसी भय के कारण वह बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल गई और भटकते हुए मंडलेश्वर पहुंच गई।

पुलिस जांच में महिला के हाथ पर कुछ नाम गुदे हुए पाए गए हैं, जिनमें उसके पति शंकर और भाई का नाम अंकित है। महिला ने यह भी बताया कि उसके माता-पिता मूंदी थाना क्षेत्र के भगवानपुरा में रहते हैं।

मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी मोइज बवाहिर ने बताया कि महिला करीब 30 से 32 प्रतिशत तक झुलसी हुई है और उसके घाव लगभग एक माह पुराने हैं। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए महिला को इंदौर रेफर किया गया है।

फिलहाल पुलिस महिला द्वारा बताए गए पते के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली की जहरीली हवा एक शहर नहीं पूरे क्षेत्र की विफलता

कांतिलाल मांडोत

दिल्ली में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं रही है, लेकिन अब यह समस्या इस हद तक पहुंच चुकी है कि इसे केवल पर्यावरणीय संकट कहना कम होगा। यह एक मानवीय त्रासदी का रूप ले चुकी है। हालिया अध्ययन ने एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर किया है कि राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर सिर्फ दिल्ली की देन नहीं है। करीब 65 फीसदी प्रदूषण शहर के बाहर से आता है, खासतौर पर एनसीआर के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों से। दिल्ली अपने स्तर पर केवल 35 फीसदी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा बदनाम भी दिल्ली ही होती है और सबसे ज्यादा मार भी यहीं के लोगों को झेलनी पड़ती है।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इसे प्रदूषण के मामले में बेहद संवेदनशील बनाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों, खेतों और शहरी इलाकों से उठे धुएं और धूल को दिल्ली में लाकर पटक देती हैं। सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि ठंडी हवा के कारण वातावरण में ऐसी परत बन जाती है जो प्रदूषक कणों को ऊपर उठने नहीं देती। नतीजा यह होता है कि दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे बेहद सूक्ष्म कण कई गुना खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं।

नई स्टडी बताती है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली के भीतर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लोकल पीएम 2.5 प्रदूषण का करीब आधा हिस्सा बनाता है। यह योगदान इंडस्ट्री, निर्माण कार्यों और कचरा या ईंधन जलाने जैसे स्रोतों से भी ज्यादा है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ट्रैफिक जाम में फंसे वाहन घंटों धुआं उगलते रहते हैं। पुरानी डीजल गाड़ियां आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं और सार्वजनिक परिवहन अभी भी जरूरत के मुकाबले अपर्याप्त है। लेकिन इन सबके बावजूद कुल मिलाकर बाहरी प्रदूषण ही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आता है।

रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि दिल्ली की प्रदूषण समस्या को केवल शहर की सीमाओं के भीतर रहकर हल नहीं किया जा सकता। यह एक क्षेत्रीय समस्या है और इसका समाधान भी क्षेत्रीय स्तर पर ही संभव है। दिल्ली सरकार चाहे जितने प्रतिबंध लगा ले, अगर एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में हालात नहीं सुधरते तो राजधानी को राहत नहीं मिल सकती। यही वजह है कि हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। सर्दी आते ही हवा जहरीली हो जाती है, स्कूल बंद होते हैं, निर्माण कार्य रुकते हैं, गाड़ियां सड़कों से हटाई जाती हैं और कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर सामान्य मान लिया जाता है।

हालांकि पराली जलाने के मोर्चे पर 2025 की सर्दी ने एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान पराली जलाने से दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में करीब 10.6 फीसदी की कमी आई है, जो 2024 की तुलना में एक बड़ी राहत मानी जा सकती है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जब पराली जलाने का सबसे ज्यादा असर होता है, उस दौरान 2025 में इसका औसत योगदान 4.9 फीसदी रहा जबकि 2024 में यही आंकड़ा 15.5 फीसदी था। यह बताता है कि अगर नीतियां सही हों और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। इसके बावजूद 12 नवंबर 2025 को एक दिन ऐसा भी आया जब पराली से प्रदूषण का योगदान 22.47 फीसदी तक पहुंच गया, जो यह याद दिलाने के लिए काफी है कि खतरा अभी टला नहीं है।

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का असर अब केवल आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत तक सीमित नहीं रहा। यह लोगों की जिंदगी छीन रहा है। अस्पतालों में अस्थमा, एलर्जी, हृदय रोग और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित होने से पहले ही कमजोर हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए यह हवा मौत को दावत देने जैसी है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर इसका असर अलग और बेहद खतरनाक है। कई शोध यह संकेत दे चुके हैं कि वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

यह संकट सामाजिक असमानता को भी गहराता है। अमीर लोग एयर प्यूरीफायर, बंद गाड़ियां और महंगे इलाज का सहारा ले सकते हैं, लेकिन गरीब और मजदूर वर्ग के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। खुले में काम करने वाले, सड़क किनारे रहने वाले और झुग्गियों में बसे लोग इस जहर को सबसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं। उनके लिए प्रदूषण कोई मौसम नहीं बल्कि रोज की मजबूरी है।

सरकारें भी इस स्थिति में अक्सर मजबूर नजर आती हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे उपाय कागजों पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर सीमित ही रहता है। ऑड ईवन, पटाखों पर प्रतिबंध और निर्माण कार्यों पर रोक जैसे फैसले तात्कालिक राहत देते हैं, स्थायी समाधान नहीं। असल जरूरत इस बात की है कि दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्य मिलकर एक साझा रणनीति बनाएं, जिसमें जवाबदेही तय हो और राजनीतिक इच्छाशक्ति साफ नजर आए।

अगर आगे की राह की बात करें तो यह साफ है कि केवल एक क्षेत्र या एक सरकार के बूते यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन को इतना मजबूत और सुविधाजनक बनाना होगा कि लोग निजी गाड़ियों से दूरी बनाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना होगा। उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर जाना ही पड़ेगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बननी चाहिए। कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक और उसके लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है। किसानों को पराली न जलाने के लिए केवल दंड नहीं बल्कि व्यवहारिक और आर्थिक विकल्प भी देने होंगे।

इस लड़ाई में नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है। जब तक समाज खुद यह नहीं मानेगा कि स्वच्छ हवा उसका अधिकार है और जिम्मेदारी भी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। हर छोटी आदत मायने रखती है। कारपूल करना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, कचरा न जलाना और पेड़ों की रक्षा करना जैसे कदम किसी एक दिन में चमत्कार नहीं करेंगे, लेकिन लंबे समय में यही बदलाव की नींव बनेंगे।

दिल्ली की हवा आज लोगों से त्राहिमाम करवा रही है। सांस लेना एक संघर्ष बन गया है। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हैं और बुजुर्ग घरों में कैद हो चुके हैं। अगर अब भी इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। हवा पर किसी एक शहर का हक नहीं होता और उसकी जिम्मेदारी भी किसी एक पर नहीं छोड़ी जा सकती। दिल्ली की जहरीली हवा यह साफ संदेश दे रही है कि अब आधे अधूरे उपाय नहीं, बल्कि ठोस और साझा समाधान का समय आ चुका है।

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाना किया शुरू

प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस महकमा भी रहा उपस्थित

माही की गूंज, आम्बुआ।

क़स्बे में बहुप्रतीक्षित अतिक्रमण हटाओ अभियान जो कि हर बार चलने के पूर्व ही बंद हो जाता रहा था इस बार 5 जनवरी को प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती दिखाई तथा हटाने की कार्यवाही शुरू की है जिसका कुछ स्थानों पर विरोध भी किया गया, मगर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया,शाम हो जाने के कारण आगामी दिनों में पुनः अभियान चलाया जाएगा।

मिली जानकारी अनुसार आम्बुआ क़स्बे में अस्थाई तथा स्थाई रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत द्वारा विगत वर्षों से नोटिस जारी किए जा रहे थे मगर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया , पिछले साल जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था मगर विरोध के कारण मुहिम को रोक दिया गया, कार्य वाही ठंडे बस्ते में डाल दी गई, पुनः मांग उठने पर पंचायत द्वारा नोटिस जारी किए गए उसके बाद भी कोई असर दिखाई नहीं दिया तब कहीं जाकर 5 जनवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री तपीस पाण्डेय के निर्देशानुसार कार्य वाही शुरू की गई है हालांकि इसका कुछ स्थानों पर विरोध भी किया गया मगर जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की उपस्थिति में बस स्टैंड क्षेत्र से लेकर वार्ड क्रमांक 6 एवं 7 में यह कार्यवाही जारी रही कुछ ने स्वेच्छा से तो कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया, शाम हो जाने के कारण शेष कार्य 7 जनवरी को किया गया। प्रशासनिक अमले में तेहसीलदार श्रीमती मंजुला डावर, क्षेत्रीय पटवारी, सरपंच सचिव पुलिस बल , चौकीदार आदि उपस्थित रहे।

प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती, पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए गए है। इसी के तहत आलीराजपुर तहसीलदार श्रीमती सविता राठी ने नगर में पतंग विक्रय दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं जोबट नगर में तहसीलदार सुनील राणा एवं नगर पालिका अधिकारियों ने अपने कार्यक्षेत्र में स्थित पतंग विक्रय की दुकानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उदयगढ़ और कट्ठीवाड़ा नगर में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा पतंग विक्रय दुकानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध मांझे की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से दुकानदारों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न बेचने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई। विदित हो कि जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत चाइना मेड नायलॉन डोर के क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की कि वे जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल वैध और सुरक्षित सामग्री का ही विक्रय करें।

गांव में एक पंगत तथा एक संगत होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो सकेगी- कैलाश अमलियार

माही की गूंज, आम्बुआ।

हमारा देश गांवों का देश है इस लिए ग्रामीण संस्कृति को बचाए रखना होगा हमें हमारी संस्कृति की रक्षा संगठित होकर करना यदि हम संगठित रहेंगे तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता है।

उक्त विचार आम्बुआ में आज आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रमुख प्रचारक कैलाश अमलियार ने प्रमुख वक्ता के रूप में व्यक्त किए आगे उन्होंने ने आदिवासी भाषा में हजारों की संख्या में उपस्थित हिंदू समाज के समक्ष अनेक चुनौतियों पर विचार रखे तथा बताया कि क्षेत्र में चल रहे धर्म परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए किसी लालच में आकर अपना धर्म न बदलें। आगे उन्होंने ने बताया कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वृक्ष कम होते जा रहें जिससे आक्सीजन की कमी हो रही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, उसी के साथ साथ अपनी जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट भी पहनना चाहिए , हमारे वाद्ययंत्र हमारी संस्कृति की पहचान है उसे अन्य जगहों पर नहीं बजाना चाहिए। हम हमारी ग्रामीण संस्कृति को बचाए रखें जिसके लिए गांव में एक पंगत तथा एक संगत होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके।

सभा को जोबट से पधारी मात्र शक्ति सुश्री अनुसुइया आसोरिया ने पांच संकल्पों के विषय में बताते हुए कहा कि हम स्वदेशी उत्पाद अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण करें सादगी भरा जीवन जिएं तथा अपनी भाषा में बात चीत करें, समरसता, नागरिक अनुशासन एवं कुटुम्ब प्रबोधन यानि कि परिवार के साथ एक साथ भोजन करें, देव दर्शन आदि करना चाहिए।

कार्यक्रम के संयोजक अजय बघेल ने ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी भाषा में संबोधित करते हुए हिन्दू धर्म की व्याख्या करते हुए अपने धर्म को प्रमुखता देना चाहिये तथा अन्य धर्मों में नहीं जाने की बात कही। इसी कड़ी में ग्राम पटेल तथा पूर्व जज श्री भारत सिंह रावत ने संबोधित करते हुए संगठित होकर रहने की सलाह दी ताकि समाज का विकास हो सके।

कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मंच पर उपस्थित पटेल ,तडवी, पुजारा आदि का केशरिया दुपट्टा तथा श्रीफल दे कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम उपरांत सभी को सहभोज कराया गया। कार्यक्रम का संचालन बृजेश राठौड़ ने तथा वैभव जाधव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त कार्यकर्ता का सहयोग प्राप्त हुआ।

ग्राम पुनियावट में मोबाइल टावर लगाने की मांग

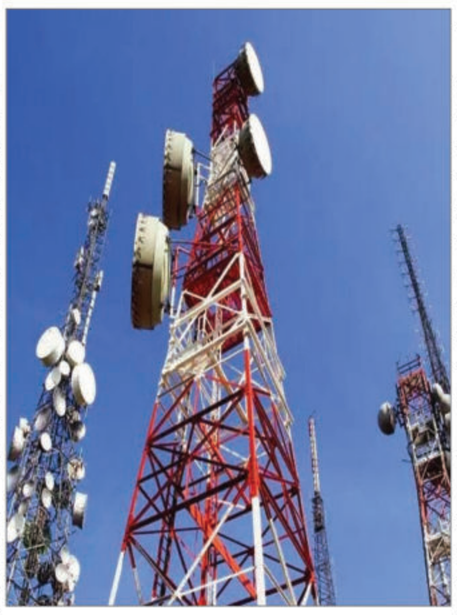

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जोबट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुनियावट अंतर्गत ग्राम पुनियावट में दूरसंचार सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर ग्राम में मोबाइल टावर स्थापित करने की मांग की है।

विधायक पटेल ने पत्र में बताया कि, ग्राम पुनियावट, विकासखंड कट्ठीवाड़ा, जिला आलीराजपुर (मध्यप्रदेश) एक आदिवासी बाहुल्य एवं दुर्गम क्षेत्र है, जहां आज तक दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क के लिए लगभग 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि नेटवर्क के अभाव में पंचायत के ऑनलाइन कार्य, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस बुलाने तथा प्रशासनिक संपर्क में गंभीर कठिनाइयां आ रही हैं।साथ ही विकास कार्यों के समन्वय में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि, ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ग्राम पुनियावट में शीघ्र दूरसंचार टावर स्थापित किया जाए, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने विधायक द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर संतोष व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है।

जमीन आवंटित हुई नहीं और सीएम से करवा दिया भूमि पूजन

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले की खाचरोद तहसील में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां नया जनपद कार्यालय बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से भूमि पूजन तो करवा लिया गया, लेकिन जिस जमीन पर भवन बनना है उसका आवंटन ही नहीं हुआ। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है।

जनपद भवन निर्माण की योजना

जनपद अध्यक्ष पंवार ने बताया कि जनपद कार्यालय का नया भवन बनना है। इसके लिए शासन ने 5.25 करोड़ रुपए मंजूर किए और निर्माण की जिम्मेदारी आरईएस (ग्रामीण यांत्रिकी विभाग) को दी गई। इसके बाद 2 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनपद की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 984 पर भूमि पूजन किया। इसी दिन 9.10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हुआ।

भूमि पूजन के बाद जमीन की तलाश

पंवार का कहना है कि वर्तमान जनपद कार्यालय के पास 7 बीघा दो बिस्वा जमीन है, जिस पर तहसील और जनपद भवन पहले से मौजूद हैं। नए भवन के लिए 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, लेकिन तहसील कार्यालय के निर्माण के कारण वहां जगह नहीं बच रही है। अब अधिकारी जनपद भवन के लिए तहसील कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर जमीन तलाश रहे हैं। पंवार ने सवाल उठाया कि जब जमीन ही उपलब्ध नहीं थी तो सीएम से भूमि पूजन क्यों करवाया गया।

प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप

जनपद अध्यक्ष ने कहा कि, बिना जमीन आवंटन के भूमि पूजन करवाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि पूजन के शिलालेख पर एजेंसी का नाम नगर परिषद लिखा गया, जबकि यह जिम्मेदारी आरईएस की थी। इस गलती को भी उन्होंने गंभीर बताया।

सीएम तक पहुंची शिकायत

पंवार ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने मांग की है कि जनपद कार्यालय का निर्माण शासकीय कार्यालयों के पास ही किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं, मामले में एसडीएम नेहा साहू से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं की समीक्षा बैठक संपन्न

माही की गूंज, आलीराजपुर।

उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, दुकानों के नियमित एवं नियमानुसार संचालन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जोबट अनुभाग स्तर पर उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) वीरेंद्र सिंह बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई।

बैठक में जोबट एवं उदयगढ़ विकासखंड में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं ने सहभागिता की।बैठक के दौरान खाद्यान्न वितरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही नवीन परिवारों की ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी ली गई। एसडीएम द्वारा माह दिसंबर 2025 में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, उनकी शेष सूची की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

अनुविभागीय अधिकारी श्री बघेल ने विक्रेताओं को निर्देशित किया कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता न हो। उन्होंने पारदर्शिता, उपभोक्ता संतुष्टि और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बैठक में विक्रेताओं की समस्याओं एवं सुझावों पर भी चर्चा की गई, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाया जा सके। इस दौरान दोनों ब्लॉक के उचित मूल्य केंद्र के विक्रेता और आमजन उपस्थित रहे।

9 महीने पहले चोरी हुई, नहीं ढूंढ पाई पुलिस

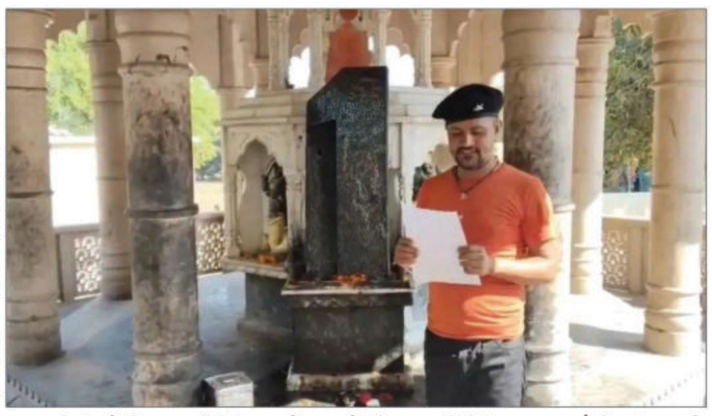

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले की झारड़ा तहसील के लोटिया जुनार्दा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद भी आम लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। लोटिया जुनार्दा गांव के किसान हरि सिंह ने नौ महीने पहले चोरी हुई दो भैंसों और एक बछड़े के मामले में कोई समाधान न मिलने पर भगवान शनि देव से न्याय की गुहार लगाई है।

किसान हरि सिंह की दो भैंसें और एक बछड़ा नौ महीने पहले चोरी हो गया था। किसान ने चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायत की, और पुलिस से जवाब भी मांगा। इतना कुछ होने के बाद भी जब नौ महीने बाद भी चोरी हुई भैंस और बछड़ा नहीं मिला, तो किसान ने न्याय के देवता भगवान शनि देव को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई।

किसान की गुहार नहीं सुनी गई

किसान की मांग है कि, भगवान शनि देव या तो उसके मवेशी लौटा दें या फिर लापरवाह अधिकारियों और चोरों को सजा दें। किसान हरि सिंह का कहना है कि इंसाफ की गुहार लगाते-लगाते उनकी चप्पलें खत्म हो गईं, लेकिन भैंस या बछड़ा नहीं मिला। बार-बार पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी, उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया।

इंसाफ के लिए शनि देव महाराज को अर्जी दी

इससे हरि सिंह और भी गुस्सा हो गए, और उन्होंने इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के पास जाने के बजाय, इंसाफ के देवता माने जाने वाले शनि देव से संपर्क करने का फैसला किया। आखिर में, वह शनि देव के दरबार पहुंचे और मंदिर पहुंचकर एक अर्जी दी, जिसमें उन्होंने शनि देव को अपनी व्यथा सुनाई। उनकी मांग है कि भगवान शनि देव या तो चोरी हुई भैंस और बछड़े को लौटा दें, या फिर दोषियों को सजा दें और इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकें।

रबी सीजन यानी बिजली विभाग के अधिकारियों की चांदी ही चांदी

चांदी की चम्मच से चाट इतनी चट रही कि जेई साहब प्रमोशन के बाद भी यही टिके हुए...

माही की गूंज, खवासा। हरिश भटेवरा

चाहे किसी प्रकार का व्यवसाय हो या फिर विभागीय कोई कार्य हो हर किसी का अपना-अपना कार्य करने का वर्ष में एक बार तो अधिक भार रहता है। यानी कि किसी व्यवसाय के लिए अपने व्यापार संबंधित अलग-अलग विशेष सीजन होती है। जैसे ठंड में होटल वालों के लिए जलेबी, राखी-दिवाली पर मिठाई की विशेष बिक्री। इसी तरह बीज की सीजन बारिश के पूर्व। स्कूल खुलने पर स्टेशनरी, शादी-ब्याह व त्योहार पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक व बर्तन, फसल उत्पादन के बाद पल्ली का व्यवसाय आदि इस तरह से प्रत्येक अपने-अपने व्यापार में व्यवसाय की एक सीजन होती है। जिसमें व्यापारी आम दिनों की अपेक्षा इस तरह की सीजन में अपना अधिक व्यापार कर अपनी अधिक आमदनी प्राप्त करता है।

इसी तरह शासकीय अलग-अलग विभागों में भी वर्ष में एक बार तो कार्य का अधिक भार सीजन अनुसार रहता है। लेकिन उक्त कार्य का भार विभाग के अधिकारी सिर्फ तनख्वाह पर ही कार्य करते हैं ऐसा नहीं है उन अधिकारियों की भी चांदी रहती है और विशेष रूप से इस तरह की सीजन में अपने विभागीय कार्य के अधिभार के साथ चांदी की चम्मच से चटनी (रिश्वत) की चाट आम दिनों के बदले अधिक चटकाई जाती है।

इसी तरह विद्युत विभाग की भी अपनी एक सीजन होती है और वह सीजन रबी फसल के दौरान होती है और इस सीजन में विद्युत विभाग का अधिकारी से लेकर चपरासी तक जमकर चांदी की चमक से चटनी की चटाई करते हैं।

विद्युत विभाग के खवासा ग्रिड की बात करें तो यहां पर जमकर चांदी की चम्मच में चटनी की चटाई हो रही है। खवासा ग्रिड पर जेई के रूप में मुकेश परमार पदस्थ है, इनका खवासा ग्रिड से ही प्रमोशन होकर एई बन गए हैं। परंतु प्रमोशन के बाद भी साहब का खवासा ग्रिड पर जेई के रूप में ही कार्यरत रहना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

विद्युत विभाग की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, यह साहब को यहां पर जमकर चांदी की चम्मच से चटनी की चटाई की चाट दातों पर ऐसी लग चुकी है कि, यहां से साहब जाने का नाम नहीं लेते हैं। और ऊपरी साठ-गांठ के साथ यही टिके हुए हैं। साहब की वर्तमान में रबी की सीजन होने से जमकर सीजन की चटनी चांदी की चम्मच से चाटी जा रही है। यहां तक साहब पर आरोप लगाया जा रहा है कि, साहब अपनी कारस्तानी में बहुत माहिर है जैसे कि, अस्थाई कनेक्शन धारी जिसमें ऐसे भी उपभोक्ता है जो जानते हैं कि, वे वैध अस्थाई कनेक्शनधारी है, लेकिन साहब की कास्तानी ऐसी कि, साहब वैध कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता से पैसा तो शासन की निर्धारित राशि अनुसार ही किसानों से ले रहे हैं लेकिन कुछ किसानों के विद्युत अस्थाई कनेक्शन की रसीद पैसे लेने के बाद भी नहीं काटी जाती है। नतीजन ऐसे किसान जो अपने आपको पैसा देकर वैध कनेक्शनधारी समझ रहे हैं, वे साहब द्वारा रसीद नहीं काटे जाने पर स्वत अवैध कनेक्शनधारी बन चुके हैं।

झाबुआ एवं इंदौर टीम कभी-कभार जांच पर आ जाती है तो टारगेट पूर्ति कर अपनी इतिश्री कर लेती है। बताया जा रहा है कि, पिछले दिनों प्याज गोदाम, मोटरसाइकिल शोरूम, आरओ फिल्टर प्लांट पर अवैध विद्युत कनेक्शन व अधिभार मिलने पर जुर्माना दिया गया था। वही एक टीम ने चार से पांच किसानों पर अस्थाई कनेक्शन की रसीद नहीं होने पर उन्हें अवैध कनेक्शन धारी दर्शाया गया है। जबकि इनमें से कुछ ने साहब को रसीद हेतु पैसे दे चुके थे।

वहीं विद्युत विभाग की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, विद्युत पोल से निर्धारित दूरी में ही कनेक्शन दिए जा सकते है लेकिन निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर कई विद्युत कनेक्शन साहब दे चुके हैं। वहीं शासन की योजनानुसार जहाँ भी विद्युत कनेक्शन के चलते अधिभार हो गया हो वहां ट्रांसफार्मर अधिभार वाले बदलने का प्रावधान है वह भी निशुल्क, लेकिन साहब अधिभार वाले तथा निःशुल्क ट्रांसफॉर्म लगाने पर वहां के कनेक्शन धारी किसानों से एक लाख व उससे अधिक तक की राशि अवैध रूप से वसूली जाती है। वहीं कई जगह क्षेत्र में विद्युत पोल शिफ्टिंग करने के बदले बिना रसीद के ही 13 से 15 हजार रुपए तक प्रति पोल लेकर अपना काम कर लेते हैं और विद्युत कंपनी को हजार से लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं।

वर्तमान में पिछले डेढ़ माह से रबी की सीजन में किसानों द्वारा खेतो में पियत की जा रही है इस दौरान साहब एवं उनकी टीम चप्पे-चप्पे जाकर वैध कनेक्शनधारियो के भी मोटरे तोक कर ला रहे हैं और वसूली कर रहे हैं। वहीं ऐसे कनेक्शनधारी जो साहब को पैसे देते हैं पर रसीद नही देते हैं उन पर साहब की बड़ी मेहरबानी बनी रहती है।

परमार साहब पिछले आठ वर्षो से अपने प्रमोशन के बाद भी यहां टिके हुए हैं विभाग की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, तलावली, सेमलिया (थांदला), कोटनाई आदि जगह के खवासा ग्रिड पर आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ है। साहब ने उक्त अपने मापदंड के अनुसार पदस्थ कर 15-15 हजार रुपए तक की वसूली की है। जानकारी रखने वाले यह भी बताते हैं कि, साहब ने चार पहिया वाहन जो ग्रिड से फिल्ड में कार्य करने हेतु लगा रखा है वह भी किसी परिवार के नाम से ही है। जानकारी रखने वाले यहां तक बताते हैं कि, जो गाड़ी किराए पर रखी गई है उसको आउटसोर्स कर्मचारी ही चलाता है जबकि गाड़ी का चालक गाड़ी मालिक की तरफ से ही होता है और भाड़े में चालक के भी पैसे विद्युत कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। साहब, कंपनी की गाड़ी का दुरुपयोग कर प्रतिदिन अपनी निजी आवाजाही हेतु प्रतिदिन थांदला अपने निवास पर जाते हैं और सुबह उसी गाड़ी से आते हैं।

जानकारी देने वाले सूत्र ने बताया कि, आगे और ऐसी जानकारी देंगे जिसमें साहब की ओर भी कारस्तानी सामने आएगी।

कलेक्टर के आदेश पर जब लोग प्रभावी प्रतिक्रिया देने लगे...? तब तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी झाबुआ जिले और इस जिलेवासियों में कई खुबियां है। मगर जब बात अपना मत रखने की आती है तो फिर वे बेबाक होकर अपना मत रख ही देते है। फिर चाहे उनकी इस बेबाक राय पर अमल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जब राय देने वालों में किसी एक तबके का बहुमत ज्यादा हो तो फिर उस राय को दरकिनार करना उचित तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी विद्वानों के निर्णय भी गलत हो जाते है, लेकिन बुद्धीजीवी और विद्वान अपने निर्णयों पर आने वाली प्रतिक्रिया को स्वीकार कर अपने निर्णयों को बदल भी लिया करते है।

वर्तमान में शीत ऋतु अपने पूरे वैग पर है और इसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में या तो स्कूलों की छुट्टीयां कर दी गई है या फिर स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश के करीब दो दर्जन से अधिक जिलों में इस तरह के निर्णय लिए गए है। हालांकि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सही भी है और वर्तमान स्थितियों के हिसाब से जरूरत भी। क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वैसे तो हर साल ही शीत ऋतु में सर्दियों का अवकाश घोषित होता है, लेकिन इस बार शीतकालीन छुट्टियों के बाद मौसम ने करवट ली है और पारा लगातार गिरता जा रहा है। स्थितियों को भापतें हुए प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारियों या कलेक्टर ने या तो शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया है या फिर स्कूलों के समय में भारी परिवर्तन करते हुए दोपहर में कक्षाएं लगाने के आदेश जारी किए है।

वर्तमान में कलेक्ट्रेरेट झाबुआ से भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए, लेकिन आमजन व पालकों के बीच यह आदेश ठंडी में गर्म चर्चाओं का विषय बन गए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार '' शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना के आदेश अनुसार झाबुआ जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई एवं अन्य समस्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की प्ले ग्रुप/ प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के छात्र-छात्राओं के लिए 6 जनवरी से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. बामनिया ने बताया कि, उक्त अवधि में संबंधित कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय संचालन स्थगित रहेगा। जबकि अन्य कक्षाएं पूर्व में जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर संचालित होती रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जब कलेक्टर का यह आदेश कलेक्ट्रोरेट के सोशल मीडिया फेसबुक अकांउट से जारी हुआ तो जिलेवासियों की प्रतिक्रिया आना भी तय थी। जब कलेक्ट्रोरेट के इस सोशल मीडिया अकांउट से यह आदेश जारी हुए तो कई लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया में तरह-तरह की टिप्पणियां भी की जो समर्थन में होने के बावजूद विरोध दर्शा रही थी।

पहला तो यह कि, जो आदेश कलेक्टर ने जारी किए वह सिर्फ प्ले ग्रुप/ प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के छात्र-छात्राओं के लिए है। जिनकी औसत उम्र लगभग आठ वर्ष मानी जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल कलेक्टर के इस आदेश पर एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि '' 1 दिन में न्यूनतम तापमान 12.4 से 8.8 हो गया, यह सरकारी मौसम विभाग का आंकड़ा है। शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। क्या यह सिर्फ कक्षा 3 तक के बच्चों पर ही असर करेगी कड़कड़ाती ठंड... !'' इसी तरह किसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, क्या ठंड का असर सिर्फ तीसरी तक के बच्चों पर ही पड़ेगा, 4 थी से लेकर 8 वीं तक के बच्चे क्या सुपर मेन है...?''। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते है कि '' स्वागत योग्य निर्णय, लेकिन 1 से 8 तक होना चाहिए और 9 से 12 तक का समय 11 बजे तक होना चाहिए, अंतिम और महत्वपूर्ण बात की आँगनवाड़ी के बच्चों के बारे में भी विचार करना चाहिए।''

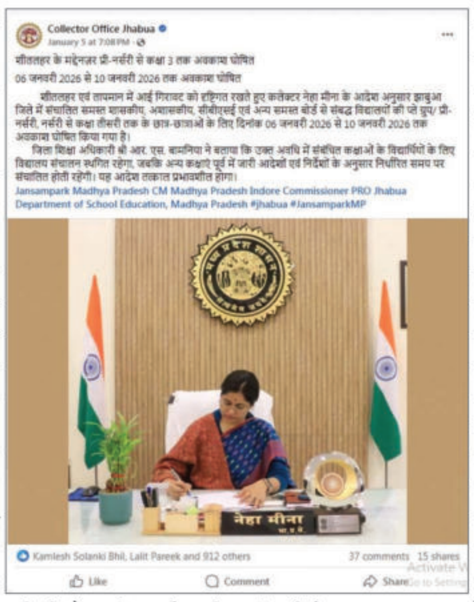

हालांकि कलेक्टर द्वारा एक अलग आदेश जारी कर जिले की सभी आंगनवाड़ियों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। आदेश पर टिप्पणी करते हुए एक युजर लिखते है कि '' मेम 8 वीं तक छुट्टी होना चाहिए शीत लहर अधिक है, और 9 से 12 का समय चेंज होना चाहिए।'' इसी तारतम्य में एक सोशल मीडिया यूजर ने आदेश का उपहास उड़ाते हुए लिखा कि, '' नहीं मेडम यह गलत बात है, छुट्टी 1 ली से 12 वीं तक रखनी चाहिए। ठंड बहुत है नहाने का मन भी नहीं कर रहा है।'' इसी तरह एक महिला यूजर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दे रही है कि, '' माननीय कलेक्टर मैडम मेरी एक बेटी पहली कक्षा में है और दूसरी पांचवी में पूरे जिले में शीतलहर बढ़ जाने के कारण आपने प्ले से तीसरी कक्षा तक10 तारीख तक अवकाश घोषित किया जो अगर आठवीं कक्षा तक होता तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरे घर में छोटी बेटी एवं बड़ी बेटी के बीच शीत युद्ध चालू हो गया है कृपया आप समाधान कीजिए।'' अपनी प्रतिक्रिया के साथ इन्होने अपनी बेटी का एक भावुक वीडियों भी सेंड किया है जिसमें 5 वीं की वह नन्ही सी बिटिया कलेक्टर मेडम को अवकाश घोषित करने का निवेदन भी कर रही है। कलेक्टर के आदेश पर इस तरह की चटपटी प्रतिक्रियाओं की अच्छी खासी संख्या है मगर ये वे लोग है जो सोशल मीडिया पर बने हुए है। इनके अलावा भी आमजन की इसी तरह की प्रतिक्रिया है कि, क्या ठंड सिर्फ 3 री तक के बच्चों को ही प्रभावित करती है? बात सही भी है। क्या यही आदेश 8 वीं तक के बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ठंड तो इन बच्चों को भी लगती ही होगी।

वहीं दूसरी और पड़ोसी जिलों में भी जिला कलेक्टरों ने इसी तरह के आदेश जारी किए लेकिन उनमें और झाबुआ जिला कलेक्टर के आदेश में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने प्ले ग्रुप/ प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया। जबकि दूसरी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को कड़कड़ाती ठंड में पूर्ववत स्कूल जाना पड़ रहा है। जबकि पड़ोसी जिलों में कलेक्टरों ने जो आदेश जारी किए है वे बिल्कुल ही अलग और निर्विवादित है। खरगोन जिला कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए समझदारी भरा निर्णय लिया और आदेश जारी किए जिसमें खरगोन जिले में संचालित शासकीय, अशासकीय, सीबीएससी, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं समस्त बोर्ड संबंधित विद्यालयों की कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक एवं आंगनवाड़ी के छात्र-छात्राओं हेतु दिनांक 06 जनवरी से 15 जनवरी तक समस्त समस्त शैक्षणिक संस्थाएं प्रातः 9 बजे से पहले संचालित नहीं होगी। मतलब खरगोन जिले की समस्त शैक्षणिक संस्था की कक्षा नर्सरी से लेकर 12 तक 9 बजे बाद से संचालित होगी। इसे समझादारी भरा फैसला इसलिए भी कहा जा सकता है कि, पहला तो यह कि बच्चे कड़ाके की ठंड से बच सकेंगे और दूसरा यह कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित भी नहीं होंगी।

इसी तरह बड़वानी जिले में भी शीत लहर को देखते हुए कक्षा नर्सरी से 8 वीं तक के बच्चों की कक्षाएं प्रातः 10 बजे के बाद लगाने के आदेश है। जबकि झाबुआ जिले में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है और यही कारण है कि, आदेश जारी करने के बाद से ही कलेक्टोरेट के सोशल मीडिया अकांउट पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब प्रशासन के जारी आदेश पर इस तरह की प्रभावी प्रतिक्रिया आमजन की तरफ से मिल रही है तो फिर यह विचारणीय है कि, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? प्रशासन और जिला कलेक्टर को चाहिए कि, वे अपने आदेशों पर पुर्नविचार करे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए भले ही अवकाश घोषित ना करे, लेकिन जिले की तमाम शैक्षणिक संस्थाओं की सभी कक्षाओं का समय परिवर्तन जरूर करे। जिससे बच्चे ठंड से सुरक्षित भी रह सके और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों का कोई नुकसान भी ना हो। वरना सोशल मीडिया पर तो आमजन यह भी कह रहे है कि, '' सरकार अपनी नहीं, प्रशासन भी अपना नहीं है, लेकिन बच्चे तो अपने है, कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ है, चाहें तो स्कूल भेजे चाहे ना भेजे।''

माही की गूंज परिवार का वार्षिक मिलन समारोह सम्पन्न

माही की गूंज, मेघनगर।

कैलेंडर नव वर्ष पर रविवार 4 जनवरी को एम3/स्नेह पैलेस होटल मेघनगर में माही की गूंज परिवार का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। उक्त आयोजन में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में थांदला जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेमसिंह चौधरी, विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला पत्रकार संघ के संरक्षक हरिशंकर पवार उपस्थित थे। माही की गूंज के संस्थापक व प्रधान संपादक संजय भटेवरा की अध्यक्षता में संपन्न हुए समारोह में झाबुआ-आलीराजपुर जिले के सभी माही की गूंज परिवार के सदस्य (संवाददाता) उपस्थित रहे।

समारोह में विशेष अतिथि हरिशंकर पवार द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि, माही की गूंज 8वे वर्ष के पड़ाव पर निरंतर अंकों के प्रकाशन के साथ पहुंच चुका है, जो झाबुआ जिले में एक बड़ी उपलब्धि है। आज झाबुआ के छोटे से गांव खवासा से अखबार का प्रकाशन किया जा रहा है जो बड़े अखबार के स्वरूप में प्रकाशित होकर प्रदेश व देश स्तर तक सोशित व पीड़ितों की आवाज पहुँचा रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ श्री पवार ने माही की गूंज के 8वें वर्ष के पड़ाव पर पहुंचने पर माही की गूंज परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही जिस रफ्तार से माही की गूंज अपनी लेखनी के चलते प्रसिद्धि हासिल कर चुका है उम्मीद है भविष्य में यह अखबार साप्ताहिक अखबार से दैनिक अखबार का स्वरूप भी जरूर लेगा। श्री पवार ने सभी सदस्यों को कहा कि, निष्पक्ष पत्रकारिता भले ही काटो भरी हो पर यह निष्पक्ष पत्रकारिता ही पाठकों के विश्वास पर खरा उतरकर माही की गूंज अपना विश्वास कायम कर चुकी है।

मुख्य अतिथि प्रेमसिंह चौधरी ने संबोधित करते हुए सर्वप्रथम माही की गूंज के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही श्री चौधरी ने कहा, माही की गूंज एक ऐसा अखबार है जो जिले की पत्रकारिता के स्तंभ रहे यशवंत जी घोड़ावत की प्रेरणा के साथ प्रकाशित हो रहा है। और यह अखबार यशवंत जी घोड़ावत की प्रेरणा पर खरा उतरकर आज पाठकों में अपना विश्वास कायम कर चुका है। प्रति गुरुवार को माही की गूंज अखबार का इंतजार पाठकों में रहता है, क्योंकि माही की गूंज ही ऐसा अखबार है जिस में स्थानिय व अंदर की खबरें पूरे सच के साथ व विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलती है। इसीलिए पाठकों को गुरुवार का इंतजार रहता है कि, उसमें उन्हें सच व खास खबरें पढ़ने को मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि, पत्रकार की स्याही अपनी, श्रम अपना, साहस अपना सब कुछ अपना लगाता है, जबकि बाकी तीन स्तंभ को सर्व सुविधा मिलती है, परंतु चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कोई सुविधा नहीं मिलती फिर भी आम लोगों के हक में सदैव खड़ा रहकर अपनी लेखनी का निर्वहन पत्रकार करता है। श्री चौधरी ने माही की गूंज के प्रधान संपादक संजय भटेवरा व टीम के साहस को धन्यवाद देते हुए कहा कि, अन्य मुद्दों की तर्ज पर जनहित में आधार कार्ड मामले में भी अवैध वसूली के संबंध में समाचार प्रकाशित किये। जिससे आधार संचालक की काली कमाई बंद होती देख प्रशासन ने असल आरोपियों को संरक्षण देकर फरियादी बना दिया और जनता की आवाज बने माही की गूंज प्रतिनिधि और प्रधान संपादक पर झूठा मामला दर्ज कर अपनी भ्रष्ट पृष्ठ भूमि को प्रदर्शित किया है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। माही की गूंज के साहस को बधाई देते हुए कहा कि, पाठकों का विश्वास आपके साथ है ऐसे में भ्रष्ट कितने भी अपनी ताकत लगाए लेकिन जीत सच्चाई की ही होगी। अतिथियों के उद्बोधन के बाद सभी माही की गूंज सदस्यों को प्रेस कार्ड व पैन देकर उन्हें सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती व यशवंत जी घोड़ावत की प्रतिमा पर पुष्पहार के साथ पूजा अर्चना की। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत झाबुआ-आलीराजपुर जिले से आए सभी सदस्यों ने पुष्पमाला पहनाकर किया।

सभी माही की गूंज सदस्यों के सम्मान के बाद माही की गूंज के प्रधान संपादक संजय भटेवरा ने परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि, माही की गूंज किसी एक का नहीं बल्कि यह अखबार पूरे परिवार का है। साथ ही यह अखबार परिवार के साथ सभी पाठकों का है जो उनके विश्वास के साथ हमारी लेखनी को बल देते है। हमने सदैव घोड़ावत जी की प्रेरणा के साथ हमारी निष्पक्ष लेखनी का निर्वहन किया है और माही की गूंज पाठकों के विश्वास पर खरा उतरते हुए 7 वर्ष पूर्ण कर 8 वे वर्ष में अपना कदम रख चुका है।

श्री भटेवरा ने आस्वस्त किया कि, आगे भी हमारी निष्पक्ष कलम इसी तरह जारी रहेगी। साथ ही सभी प्रतिनिधियों से कहा कि, वे किसी संस्थान से नहीं बल्कि अपने खुद के अखबार से जुड़े है अतः हमें विज्ञापन नहीं सिर्फ समाचार चाहिए।

क्षेत्र में शोषित, पीड़ित के पक्ष में व माफिया व भ्रष्टो के विरुद्ध बेबाकी के साथ समाचार का संकलन करने की बात कही। साथ ही श्री भटेवरा ने कहा, कहीं भी अनियमित्ता के साथ कहीं अच्छे कार्य भी होते हैं, हमें अच्छे कार्य की सराहना भी करना चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं है, एक पत्रकार के लिए सिर्फ एक समाचार होता है न की नेगेटिव या पॉजिटिव। इसलिए किसी भी समाचार को न हीं नेगेटिव व न ही पॉजिटिव ले सिर्फ जो घटनाएं धरातल पर है उस घटना का तथ्यात्मक समाचार का संकलन करें। कार्यक्रम का संचालन राकेश गेहलोत ने किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422